



सबसे तेज प्रयागराज

सब पर नजर, सटीक खबर

नगर संस्करण



sabsetejprj2023@gmail.com

गुरुवार, 01 अक्टूबर 2026

वर्ष: 04, अंक: 191 पृष्ठ: 08, मूल्य: 2 रु.

प्रयागराज से प्रकाशित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

एसआईआर पर इंडी गठबंधन की हुई बैठक, बनाई रणनीति

06 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे, गठबंधन ने ईवीएम के बजाय बलेट पेपर से मतदान करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी की

नई दिल्ली/एजेंसी
विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन ने चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का फैसला किया है। गठबंधन के घटक दल 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में मार्च निकालेंगे। 06 अक्टूबर को विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। गठबंधन ने ईवीएम के बजाय बलेट पेपर से मतदान करने और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग भी की। यहाँ बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडी गठबंधन को आठवीं बैठक करीब तीन घंटे तक चली। बैठक में एसआईआर, ईवीएम-वीवीपेट, मतदाता सूची और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट), शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट), राष्ट्रीय जनता दल, माकपा, भाकपा, जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भाकपा (माले), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस (एम), एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरल कांग्रेस (जे)



एसआईआर पर दिल्ली में एक बड़ी रैली 1 नवंबर को आयोजित की जाएगी: खरगे

इनके स्थान और तारीखों का फैसला बाद में होगा। दिल्ली में एक बड़ी रैली 1 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इनमें भविष्य के चुनावों में एसआईआर से पहले की मतदाता सूची का इस्तेमाल, मतदाता सूची में हर बदलाव की पूरी पारदर्शिता, किसी नाम को हटाने से पहले सूचना और अपील का अधिकार, पात्र मतदाताओं को और अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक सहित 20 विपक्षी राजनीतिक दल शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि गठबंधन के सभी दल इन मुद्दों पर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।



प्रशासनिक कारणों से बाहर किए जाने से सुरक्षा, ईवीएम के बजाय से मतदान कराया जाना चाहिए। खरगे ने कहा कि विपक्षी दल 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालेंगे। 6 अक्टूबर को सभी विपक्षी सांसद चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे। साथ ही विपक्षी नेता अक्टूबर के दूसरे

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है और भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। चुनावों में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए ईवीएम के बजाय बलेट पेपर

बलेट से मतदान और युवाओं के लिए सरल मतदाता पंजीकरण शामिल हैं। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यप्रणाली पर सवाल बताया और उनके पद से हटाने की मांग की। खरगे ने 2023 के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित कानून का भी मुद्दा उठाया।

सप्ताह में राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगेंगे। वे राष्ट्रपति को चुनाव प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दों की जानकारी देंगे। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर में पांच बड़ी रैलियां भी आयोजित की जाएंगी।

एसआईआर से पहले की मतदाता सूची को चुनाव में प्रयोग किया जाए

खरगे ने कहा कि मतदाता सूची में बदलाव की पूरी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। एसआईआर से पहले की मतदाता सूची को भविष्य के चुनावों में इस्तेमाल करने की मांग भी उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे सूचना दी जानी चाहिए। नाम हटाने का कारण बताया जाना चाहिए। उसे प्रभावी अपील का अवसर भी मिला जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासनिक खामियों, दस्तावेजों की कमी या जानकारी के अभाव के कारण पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने से सुरक्षा की मांग की। खरगे ने दावा किया कि एसआईआर के तहत 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि नाम हटाए गए हैं तो यह भी बताया जाना चाहिए कि किसका नाम हटाया गया और क्यों हटाया गया। अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग जरूरी है। मुख्य चुनाव आयुक्त के दो सहयोगी चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में 14 बार असहमति दर्ज कराई है।



इंडी गठबंधन के सभी नेताओं ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई: राहुल

इस कानून में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को शामिल किया गया है। सरकार ने चुनाव आयोग को प्रभावित करने की व्यवस्था तैयार की है। खरगे ने आरोप लगाया कि मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में बदलाव कर युवाओं के लिए पहली बार मतदाता बनने की प्रक्रिया कठिन की जा रही है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और

सुगम होनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी नेताओं ने लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता जताई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संबंधित व्यक्ति कितना बड़ा या प्रभावशाली है। भारतीय लोकतंत्र हर व्यक्ति से बड़ा है। विपक्षी दलों ने मिलकर देश की जनता तक यह बात पहुंचाने में सफलता हासिल की है कि चुनाव चोरी किए जा रहे हैं।

गेहूं के एमएसपी में 25 रुपये की बढ़ोतरी, 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हुआ भाव

नई दिल्ली/एजेंसी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन वर्ष 2027-28 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 25 रुपये

प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इसके साथ गेहूं का एमएसपी बढ़कर 2,610 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं

का एमएसपी 2,585 रुपये प्रति क्विंटल था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रेसवार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र

मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने विपणन वर्ष 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के एमएसपी में

बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रबी फसलों के एमएसपी में

वृद्धि की है। सरकार के फैसले के तहत गेहूं के अलावा अन्य प्रमुख रबी फसलों के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। वैष्णव के अनुसार, कुसुम

के एमएसपी में सबसे अधिक 675 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके बाद रेपसीड और सरसों के एमएसपी में 413 रुपये प्रति क्विंटल

की बढ़ोतरी हुई है। मसूर के एमएसपी में 390 रुपये, जौ में 136 रुपये और चना में 83 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

Reg. No.: 0917500106

सत्यम शिवम हास्पिटल

टिकरी, कौड़िहार, प्रयागराज

संचालित सत्यम पब्लिक एजुकेशनल सोसाइटी 9/9/1A लुकरगंज प्रयागराज के द्वारा

नोट :- हमारे यहाँ हर समय विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं और सभी प्रकार का इलाज कुशलता से किया जाता है।

- 150 बेड की व्यवस्था
- आई0 सी0 यू0
- एन0 आई0 सी0यू0
- आपरेशन थियेटर
- वैन्टीलेटर, वाई0 पैप
- ओ0पी0डी0
- ई0 सी0 जी0
- डिजिटल एक्स-रे
- पैथोलॉजी
- अल्ट्रासाउण्ड
- नार्मल डिलीवरी
- आपरेशन से डिलीवरी की व्यवस्था
- 24 घंटा ऑक्सीजन की सुविधा
- 24 घंटा इमरजेंसी की सुविधा
- एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध

निर्देशक : संजय शुक्ल

सम्पर्क सूत्र : 9451181332, 9198860735

कालेज कोड 01083

सत्यम शिवम शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स

टिकरी, धरवनपुर, प्रयागराज

सम्बद्ध प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है।

हेल्पलाइन नं.: 9451181332, 9198860735

Website : <http://sssgroup.co.in>

SATYAM SHIVAM SHUBHAM GROUP OF INTITION

TIKRI PRAYAGRAJ

Course

B.A., M.A., B.Sc, M.Sc., (Ag)
B.Com., M.Com., LL.B.
B.A.LL.B., B.Pharm
D.Pharm, ITI, BTC.

संजय शुक्ल
चेयरमैन

राजकुमारी शुक्ला
निर्देशक

सीडीओ ने की विशेष संचारी रोग नियन्त्रण एवं दस्तक अभियान के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक

साफ-सफाई, फागिंग एवं एन्टीलार्वा का छिड़काव कराने के निर्देश

स्वाती मिश्रा कौशांबी। मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी ने सरस हॉल में विशेष संचारी रोग नियन्त्रण अभियान एवं दस्तक अभियान के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 संजय कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार विशेष संचारी रोग नियन्त्रण अभियान 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर,2026 तक एवं दस्तक अभियान दिनांक 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर,2026 तक संचालित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार पर प्रभावी नियन्त्रण तथा त्वरित एवं सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि संचारी रोग नियन्त्रण अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा कार्य किया जाना है। चिकित्सा एंव स्वास्थ्य

विभाग द्वारा संचारी रोगों तथा दिमागी बुखार केसेज की निगरानी (सर्विलांस)। फ्रन्ट लाइन वर्कर्स द्वारा ई-कवच पोर्टल पर डिजिटली अपलोड की गई लक्षणयुक्त व्यक्तियों की सूची में रोगियों के लक्षण के अनुसार रोगों की जाँच की व्यवस्था। वाहक निंत्रण गतिविधियों-ग्रामीण क्षेत्रों में वाहक के घनत्व का आंकलन, स्रोतों में कमी, लावारोधी गतिविधियों तथा आवश्यकतानुसार फोंगिंग आदि कार्यवाही की जायेगी। दिमागी बुखार एवं अन्य वेक्टरजनित रोगों तथा जल जनित रोगों के विषय में प्रचार-प्रसार एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों की जायेगी।

इसी प्रकार नगर विकास विभाग द्वारा-नगरीय क्षेत्रों में वातावरणीय तथा व्यक्तिगत स्वच्छता के उपायों, खुले में शौच न करने, शुद्ध पेयजल के प्रयोग तथा मच्छरों की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान



संचालित करना। खुली नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों/कचरों की सफाई करवाना। शहरी क्षेत्रों में फोंगिंग करवाना एवं सड़कों के किनारे उगी वनस्पतियों को नियमित रूप से हटाय़ा जाना आदि कार्यवाही की जायेगी। पंचायतीराज विभाग/ग्राम विकास विभाग द्वारा-ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियों के माध्यम से

रोगों के रोकथाम के लिए हूक्या करें, क्या न करेंह का सघन प्रचार-प्रसार किया जायेगा।

पेयजल स्रोतों/संसाधनों से शौचालयों की दूरी के उपाय, शौचालयों/सीवर से पेयजल प्रदूषित न होने देने के लिए आवश्यक उपाय, जलाशयों एवं नालियों की नियमित सफाई, ग्रामीण क्षेत्रों में मंरेगा फण्ड से एण्टीलार्वा छिड़काव की व्यवस्था, जल निकासी एवं साफ-सफाई, वाटर सील्ड शौचालयों की आवश्यकता, ग्राम स्तर पर कचरा निस्तारण एवं प्रबन्धन व्यवस्था का विकास एवं सभी संवेदनशील ग्रामों में स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत ग्रामों में प्रत्येक मकान में शौचालय का निर्माण कर ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त बनाना आदि किया जायेगा।

पशु पालन विभाग द्वारा-सूकर पालकों को अन्य व्यवसाय जैसे-पोल्ट्री उद्योग को अपनाने के

लिए जागरूक एवं प्रेरित करना, यथासंभव सूकरबाड़े को मानव आबादी से दूर स्थापित करवाना एवं सूकर पालकों को सूकर बाड़े की साफ-सफाई, कीटनाशक छिड़काव एवं मच्छररोधी जाली से ढकने के लिए प्रशिक्षित आदि किया जायेगा। बाल विकास एवं पुष्टहार विभाग-आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों की सूची बनाकर उनको उचित पोषहार उपलब्ध कराना तथा आवश्यकता होने पर पोषण पुनर्वास केंद्रों पर उपचार तथा पोषण पुनर्वास के लिए भेजना एवं आशा कार्यकर्त्रियों द्वारा संचारी रोग नियन्त्रण एवं दस्तक अभियान के लिए क्षेत्र में सम्पादित की जा रही समस्त गतिविधियों एवं गृह भ्रमण में आँगनवाड़ी कार्यकत्री आशा कार्यकत्री के साथ रहते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करना आदि की जायेगी।

किसानों की समस्याओं को लेकर डीएम को सौंपा झापन, 5 अक्टूबर को किसान पंचायत का ऐलान

सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। प्रयागराज जनपद के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के मंडल अध्यक्ष बबलू दूबे के नेतृत्व में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भूमि अधिग्रहण, फसल मुआवजा, खाद की उपलब्धता, धान क्रय केंद्र और आवारा पशुओं समेत किसानों से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। किसान संगठन ने सोरांव और फूलपुर तहसीलों में किसानों की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही टिकरी, मुसैमऊ, गंगागंज समेत अन्य गांवों में आवस विकास परिषद की ओर से कथित



अधिग्रहण और धारा-28 की नोटिस चस्या कर जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक लगाए जाने का विरोध किया गया। ज्ञापन में किसानों की जमीन से एक्सप्रेसवे निकाले जाने पर रोक, सिधापुर, मकदूमपुर, पूरे घासी सहित विभिन्न गांवों में चकबंदी से

देने, रबी की बुवाई के लिए समय से डीएपी और यूरिया उपलब्ध कराने तथा खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा धान क्रय केंद्र खोलने, छुट्टा पशुओं को गौशालाओं या पशुबाड़ों में भेजने, नहरों की सफाई, सरकारी अस्पतालों में गरीबों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही।

भाकिू (अराजनैतिक) ने इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 5 अक्टूबर 2026 को जिला कलेक्ट्रेट/जिलाधिकारी कार्यालय प्रयागराज में किसान पंचायत आयोजित करने की घोषणा की है।

महात्मा गांधी जी की जयंती को गरिमापूर्ण ढंग से मनाये जाने हेतु डीएम की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न



सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में महात्मा गांधी जी की जयंती को गरिमापूर्ण ढंग से मनाये जाने एवं इस अवसर पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों की तैयारियों के सम्बंध में संगम सभागार में बुधवार को बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन स्मृति व योगदान को याद करने एवं उनके कुतिल व व्यक्तित्व से प्रेरणा लेने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से नगर क्षेत्र में मूर्तियों की साफ-सफाई, नगर की साफ-सफाई हेतु स्वच्छता अभियान एवं मलिन बस्ती के आस-पास व पदियों के किनारे विशेष साफ-सफाई कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने पंचायतीराज विभाग को ग्राम पंचायतों में विशेष साफ-सफाई

कराये जाने के लिए निर्देशित किया है।

जिलाधिकारी ने सभी कार्यालयों में साफ-सफाई का कार्य कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक व बेसिक शिक्षा अधिकारी से विद्यालयों में महात्मा गांधी जी के विचार दर्शन एवं जीवन परिचय पर आधारित निबंध कला, भाषण प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चित्रकला का आयोजन कराये जाने के लिए कहा है।

इस अवसर पर सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों में राष्ट्रध्वज फहराया जायेगा तथा राष्ट्रध्वान गाया जायेगा। इसके साथ ही कार्यालयों में उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं विचार गोष्ठी एवं सामाजिक संगठनों के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन उपमा पांडेय सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दशहरा एवं दुर्गा पूजा की तैयारियों के सम्बंध में सीपी और डीएम ने की बैठक दिए निर्देश

सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया व जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की सहअध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में दशहरा एवं दुर्गापूजा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, कार्यदायी विभागों के अधिकारियों व दुर्गापूजा एवं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने विभागों से सम्बंधित कार्यों को समय से पूर्ण कर लें। उन्होंने समितियों के पदाधिकारियों से आयोजन को सकुशल सम्पन्न

कराने में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, नालियों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, पार्किंग की व्यवस्था सहित आदि व्यवस्थायें समय से कराये जाने के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिए है। जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग एवं नगर निगम के अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत कराने के निर्देश दिए है। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से निबंध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कराने के साथ ही लटक जर्जर तारों की मरम्मत, खराब ट्रांसफार्मरों को बदलने, रास्तों पर लटकते पेड़ों की टहनियों की छटाई कराने तथा नगर



निगम को स्ट्रीट लाइटो को सही कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों को संयुक्त रूप से भ्रमण करके सभी आवश्यक

व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने एवं संवेदनशील स्थानों का भी अवश्य भ्रमण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को एम्बुलेंस एवं डॉक्टरों की टीम की उपलब्धता

आपरेशन चक्रव्यूह के तहत 5 वारण्टी अभियुक्त दबोचे गए

सबसे तेज प्रयागराज कौशांबी। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये गये अभियान आपरेशन चक्रव्यूह के तहत जनपद के थाना मंझनपुर, सराय अकिल व चरवा की पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चलाकर कुल 5 वारण्टी अभियुक्तों को अमल-अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया। थाना मंझनपुर पुलिस ने अभियुक्त राजू उर्फ ओम प्रकाश पुत्र सन्तराम निवासी गोबर सहाई थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी ,वारण्टी अभियुक्त अभिलाष पटेल पुत्र कैलाश निवासी रामपुर बसोहरा थाना मंझनपुर जनपद कौशाम्बी।

थाना चरवा पुलिस ने वारण्टी अभियुक्त जितेन्द्र पुत्र सूरज पाल पासी निवासी ग्राम चरवा थाना चरवा , वारण्टी अभियुक्त राम शरन पुत्र गया प्रसाद निवासी ग्राम कटरा थाना चरवा जनपद कौशाम्बी ।

25 हजार का इनामिया अभियुक्त गिरफ्तार

सबसे तेज प्रयागराज बुलंदशहर। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना अहमदगढ पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय हैं कि दिनांक 27-07-2026 को थाना अहमदगढ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जगदीशपुर में हुई मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अहमदगढ पर मुअस-257/26 धारा 352, 109(1), 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में थाना अहमदगढ पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका हैं तथा अभियुक्त शाबिर लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बुलन्दशहर द्वारा 25 हजार रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। शाबिर पुत्र आशिक अली निवासी विवेक विहार झिलमिल कॉलोनी दिल्ली, (हाल पता- इंदगाह के पास गली न0-06 वजीर चौक शहीद नगर गाजिाबाद ।)

दो परिवार पुलिस के प्रयास से साथ रहने को हुए राजी

सबसे तेज प्रयागराज कौशांबी। परिवार परामर्श केंद्र, जनपद कौशाम्बी में कुल 6 प्रकरणों में दोनों पक्षों की कार्टसलिंग की गई। कार्टसलिंग के दौरान 2 प्रकरणों में पति-पत्नी एवं उनके परिवजनों के मध्य आपसी सहमति से सुलह-समझौता कराया गया। परिवार परामर्श केंद्र द्वारा दोनों पक्षों को पारिवारिक दायित्वों एवं आपसी सामंजस्य के महत्व के संबंध में समझाया गया। दोनों पक्षों ने भविष्य में आपसी प्रेम एवं सौहार्द के साथ जीवन व्यतीत करने की सहमति व्यक्त की। शुभकामनाओं के साथ घर भेजा गया। इसके साथ ही परिवार परामर्श केंद्र द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, साइबर अपराध से बचाव एवं मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान हेलपलाइन नंबर 112, 1076, 1090, 102, 1098, 1930 एवं 181 तथा महिला हेल्पडेस्क, एंटी रोमियो टीम एवं थानों के सीयूजी नंबरों की जानकारी दी गई।

साइबर अपराध से बचाव के सम्बन्ध में किया जागरूक

सबसे तेज प्रयागराज कौशांबी। साइबर क्राइम थाना द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मंझनपुर (डाइट) के लगभग 500 शिक्षक/शिक्षिकाओं को विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध से सम्बन्धित अपराध के बारे में बताया व जागरूक किया गया और गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 वा www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई, जिस पर तत्काल कॉल व वेबसाइट में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराने के बारे में जानकारी प्रदान की गई। जिससे आमजनमास साइबर फ्रॉड से बच सके। कार्यशाला में बताया गया कि प्रलोभन में आने के चलते लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई खो बैठते हैं इसलिए किसी भी प्रकार के प्रलोभन में न आए। इस दौरान बैंक से संबंधित, क्यूआर कोड स्कैन, वाट्सएप हैक, ओएलएक्स के माध्यम से ठगी, केवाइसी, हनी ट्रैपिंग, डुप्लीकेट एप,ऑनलाइन लोन स्कैम, केबीसी, इंटरनेट मॉडिया से ठगी, एटीएम, सेक्सटारशन, कंप्यूटर संबंधी फ्राड और बचाव के संबंध में जानकारी दी गयी व साइबर ठगी होने पर 1930 पर सूचना देने की अपील की गयी। हमें जागरूक रहने की जरूरत है ।

गाजीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

सबसे तेज प्रयागराज फतेहपुर। पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में वॉलंट/वारण्टियों की गिरफ्तारी एवं अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा एनबीडब्ल्यू पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त दीपक यादव पुत्र भोला यादव उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम मोहम्मदपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।



कलम से प्रतिभा का प्रदर्शन, तीन छात्राओं ने जीते पुरस्कार

फूलपुर के फतेहपुर माफी विद्यालय में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन

मौजी लाल रावत

फूलपुर। किताबों में पढ़े विचार जब बच्चों की अपनी कलम से कागज पर उतरे तो उनकी रचनात्मक प्रतिभा सामने आई। फूलपुर के सार्वजनिक ग्रामीण पूर्व माध्यमिक विद्यालय फतेहपुर माफी में आयोजित निबंध प्रतियोगिता में कक्षा छह से आठ तक के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को शब्दों का रूप देकर लेखन और अभिव्यक्ति क्षमता का परिचय दिया।

बुधवार को हुई प्रतियोगिता का आयोजन शिक्षक सिद्धार्थ भारद्वाज ने करवाया। विद्यार्थियों के प्रदर्शन के आधार पर कक्षा छह में प्रिया पटेल, कक्षा सात में पलक द्विवेदी और कक्षा आठ में शिवानी को विजेता चुना गया। विद्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में तीनों विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।



सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया व जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की सहअध्यक्षता में बुधवार को संगम सभागार में दशहरा एवं दुर्गापूजा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन, कार्यदायी विभागों के अधिकारियों व दुर्गापूजा एवं रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी सम्बंधित अधिकारी अपने-अपने विभागों से सम्बंधित कार्यों को समय से पूर्ण कर लें। उन्होंने समितियों के पदाधिकारियों से आयोजन को सकुशल सम्पन्न



कराये जाने के लिए कहा है। उन्होंने नगर निगम को छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने सभी सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को भ्रमण कर मेला मार्गों की कमियों को दूर कराये जाने के लिए कहा है। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज विभाग को साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है। जिलाधिकारी ने कहा कि कोई भी गैर परम्परागत कार्य नहीं होगा। फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। यातायात की व्यवस्था, डायवर्जन तथा पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित रहे। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों पर भी सुरक्षा की

पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित रहे। अपराध निरोधक, सिविल डिफेंस तथा अन्य सहयोगी विभाग के लोगो की शिफ्ट वाइस ड्यूटी लगायी जाये।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त पीयूष मोडिया ने कहा कि मेले में निकलने वाले झांकियों का एक निश्चित क्रम हो तथा उनकी उचाई ज्यादा न हो। उन्होंने पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को पार्क करने के लिए कहा है। कहा कि सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था रहेगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखे जाने के लिए कहा है। उन्होंने मानक के अनुरूप ही साउंड बजाये जाने के लिए कहा है, जिससे कि किसी को भी कोई परेशानी न हो।

पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का केस रद्द

हाईकोर्ट ने कहा- शादी के वादे पर बना हर संबंध दुष्कर्म नहीं, शुरु से झूठा वादा साबित होना जरूरी

विधि संवाददाता
सबसे तेज प्रयागराज
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर अमित कुमार के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने आरोपपत्र और वाराणसी की अदालत में लंबित पूरी कार्यवाही निरस्त करते हुए अर्जी मंजूर कर ली। मधुरा के कोसी कला निवासी युवती ने आठ जनवरी 2020 को वाराणसी के महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 2013 में कोसी कला में तैनात रहे इंस्पेक्टर अमित कुमार ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा और अपनी पहली शादी की बात

झिपाई। युवती का आरोप था कि सितंबर 2019 में उसे वाराणसी के एक होटल में बुलाकर मिल्क शेक में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया गया। आरोप यह भी था कि उसकी अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराया गया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके खिलाफ अमित कुमार ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर पूरी कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी।

शुरू से झूठा वादा साबित होना जरूरी
हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का वादा कर बनाए गए हर संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। ऐसे मामले में

यह साबित करना जरूरी है कि संबंध बनाते समय आरोपी का शादी करने का इरादा ही नहीं था और महिला की सहमति केवल इसी झूठे वादे के आधार पर ली गई थी। कोर्ट ने कहा कि युवती 27 वर्ष की शिक्षित वयस्क थी और 2013 से आरोपी को जानती थी। वह बिना किसी को बताए अकेले विमान से वाराणसी गई और होटल में आरोपी के साथ रुकी। इसके बाद भी उसने तत्काल कोई शिकायत नहीं की और आरोपी के संपर्क में बनी रही। वह आरोपी के मेरठ स्थित पैतृक घर भी गईं, जहां भी शिकायत किए जाने का कोई तथ्य सामने नहीं आया।

आरोपी ने शादी करने से कभी इनकार नहीं किया था। उसकी पहली पत्नी से तलाक़ 14 दिसंबर 2023 को मेरठ की पारिवारिक अदालत से मंजूर हुआ

कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट का भी उल्लेख किया, जिसमें युवती ने लिखा था कि वह आरोपी के तलाक़ होने तक इंतजार करेगी। इससे अदालत ने माना कि उसे आरोपी की पहली शादी की जानकारी थी। अदालत के समक्ष पेश फोटो में भी दोनों साथ नजर आए।

हाईकोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि ब्लैकमेलिंग के आरोप से जुड़े कथित अश्लील फोटो-वीडियो न तो जांच में सामने आए और न ही पुलिस उन्हें बरामद कर सकी।

आरोपी ने शादी करने से कभी इनकार नहीं किया था। उसकी पहली पत्नी से तलाक़ 14 दिसंबर 2023 को मेरठ की पारिवारिक अदालत से मंजूर हुआ

कीमती जमीन का कम मुआवजा देने पर किसानों में नाराजगी

भाकियू टिकैत की किसान सभा में विंध्य एक्सप्रेसवे पर हुई चर्चा

सबसे तेज प्रयागराज

फूलपुर। विंध्य एक्सप्रेसवे के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण और उसके एवज में दिए जा रहे मुआवजे का मुद्दा बुधवार को भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) की किसान सभा में प्रमुखता से उठा। किसानों ने आरोप लगाया कि कीमती जमीन के बदले अपेक्षाकृत कम मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण में किसानों के हितों का ध्यान रखने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। यूनियन के कैप कार्यालय मियां का पुरी में आयोजित किसान सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भाकियू टिकैत के जिलाध्यक्ष रमोज नकवी ने कहा कि एक्सप्रेसवे के लिए ली जा रही जमीन उनके लिए महज खेत नहीं, बल्कि उनकी आजीविका



का प्रमुख साधन है। किसानों के मुताबिक जमीन की मौजूदा कीमत और उसके बदले मिलने वाले मुआवजे में अंतर होने से प्रभावित परिवारों के सामने भविष्य को लेकर चिंता खड़ी हो रही है। किसानों ने मांग की कि भूमि अधिग्रहण में बाजार

मूल्य को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा निर्धारित किया जाए। जिलाध्यक्ष रमोज नकवी ने किसानों से जुड़े मुद्दों को संगठन के स्तर पर उठाने की बात कही। सभा में संगठन की आगामी गतिविधियों और स्थानीय समस्याओं को लेकर भी विचार-

साइबर अपराध पर पुलिस का शिकंजा

पीड़िता के खाते में वापस कराए गए 3 लाख रुपये

सबसे तेज प्रयागराज

फतेहपुर। जनपद में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना बिंदकी साइबर टीम ने साइबर ठगी की शिकार पीड़िता रंजना पुत्री चन्द्रशेखर, निवासी पुरानी बिंदकी मीरखपुर के खाते में फ्रॉड की तीन लाख रुपये की धनराशि वापस कराई है। धनराशि वापस मिलने पर पीड़िता ने पुलिस प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है।

पुलिस अधीक्षक फतेहपुर अभिमन्यु मांगलिक एवं अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी बिंदकी के पर्यवेक्षण में थाना बिंदकी

50 हजार के इनामिया वाछित अभियुक्त कर्नाटक से किया गया गिरफ्तार

सबसे तेज प्रयागराज

फतेहपुर । थाना बिन्दकी पर वादी मुकदमा रामसिंह पुत्र रामगोपाल निवासी हरदौली थाना बिन्दकी फतेहपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 18 जून को मुकदमा पंजीकृत किया गया था। वाछित अभियुक्त रोहित पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी हरदौली थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर उम्र करीब 40 वर्ष द्वारा वादी मुकदमा उपरोक्त के भाई शिवदयाल उम्र करीब 70 वर्ष को गांधी गलौज के विरोध करने पर लोहे के दरवाजे पर सिर पटक पटक कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त रोहित उपरोक्त लगानार वाछित चल रहा था। अभियुक्त की



साइबर टीम ने साइबर शिकायत संख्या 33109260255112 व 33109260255415 पर प्रभावी कार्यवाही करते हुए यह सफलता अर्जित की। प्रभारी निरीक्षक शैलेश कुमार सिंह, उ0नि0 संदीप यादव, म0उ0नि0 ज्योति

अहिरवार, कां0 धर्मेन्द्र लोधी व कां0 अजीत कुमार की टीम ने विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पीड़िता की धनराशि वापस कराई। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में दिनांक 28.09.2026 से

12.10.2026 तक साइबर सेल एवं साइबर थाना की टीम द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 1930 हेल्पलाइन अथवा एन0सी0आर0पी0 पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में होल्ड धनराशि को शीघ्र पीड़ितों के खातों में वापस कराने की कार्यवाही की जा रही है। साइबर फ्रॉड के पीड़ित अपनी शिकायत में होल्ड धनराशि की जानकारी व विधिक प्रक्रिया हेतु साइबर थाना, चांदमारी, फतेहपुर में संपर्क कर सकते हैं। अभियान के दौरान साइबर थाना परिसर में प्रतिदिन प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक विशेष कैप भी संचालित किया जा रहा है।

50 हजार के इनामिया वाछित अभियुक्त कर्नाटक से किया गया गिरफ्तार



गिरफ्तारी हेतु पूर्व में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक द्वारा 725,000/- का पुरस्कार घोषित किया गया था, जिसे बाद में पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा बढ़ाकर 750,000/- कर दिया गया।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु

मांगलिक के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के निकट फतेहपुर लाकर दाखिल करते हुए बुधवार को गिरफ्तार अभियुक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

यूपीआईटीएस-2026 ने दुनिया के सामने रखी उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक तस्वीर

नोएडा, उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर पांच दिनों तक देश-दुनिया के कारोबारियों, निवेशकों, खरीदारों, उद्यमियों और आमजन से गुलजार रहा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 अब भले ही संपन्न हो चुका है, लेकिन इसके जरिए उत्तर प्रदेश के उत्पादों, उद्यमिता, निवेश संभावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को मिला वैश्विक मंच आने वाले समय में प्रदेश की कारोबारी गतिविधियों को नई दिशा देता दिखाई देगा। 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपीआईटीएस-2026 ने उत्तर प्रदेश की बदलती औद्योगिक और कारोबारी तस्वीर को देश-दुनिया के सामने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया।

पांच दिवसीय आयोजन में 5.99 लाख से अधिक आगंतुकों की मौजूदगी रही। देश-विदेश के खरीदारों और प्रदेश के उद्यमियों के बीच 41,500 से अधिक बी2बी बैठकें हुईं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों में करीब 4,400 एमओयू हुए। इन कारोबारी समझौतों और चर्चाओं से लगभग 6,500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव तथा 15,500 करोड़ रुपये के संभावित कारोबार की संभावनाएं सामने आईं। इस तरह यूपीआईटीएस प्रदेश के उत्पादों को बाजार से और उद्यमियों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने वाले प्रभावी मंच के रूप में उभरा। यूपीआईटीएस में उत्तर प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों और आधुनिक उद्योगों का ऐसा संगम देखने को



मिला, जिसमें एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) से लेकर स्टार्टअप, एमएफएमई, निर्यातक इकाइयों, युवा उद्यमियों और बड़े औद्योगिक समूहों तक को एक ही मंच मिला। प्रदेश के अलग-अलग

जिलों की विशिष्ट पहचान वाले उत्पादों ने विदेशी खरीदारों और निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया। ट्रेड शो ने यह भी दिखाया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक

सेवा और समर्पण की मिसाल रहे माधवराव सिंधिया : प्रदीप मिश्रा



कानपुर, माधवराव सिंधिया का जीवन जनसेवा और समाज के जरूरतमंद वर्गों के प्रति समर्पण की मिसाल रहा है। उनकी पुण्यतिथि पर स्मारिक बच्चों के बीच सेवा कार्य करना उनके विचारों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह बातें बुधवार को श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्मारक समिति के अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने फूलबाग बाल भवन स्थित स्मारिक सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में कही।

स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्मारक समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत स्वर्गीय सिंधिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इस दौरान वक्ताओं ने उनके जनसेवा के प्रति समर्पण और समाज के लिए किए गए कार्यों को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि सिंधिया के कार्य और समाज के प्रति उनका स्नेह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणादायी रहेंगे।

इस अवसर पर स्मारिक सेंटर के बच्चों को पौष्टिक आहार वितरित किया गया। आयोजकों और समाजसेवियों ने बच्चों को अनार, केला, सेब और संतरा समेत बिस्किट, चिप्स और चॉकलेट के पैकेट बांटे। बच्चों के बीच सामग्री वितरण के दौरान आयोजकों ने उनके साथ समय भी बिताया। भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने कहा कि विशेष बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखना समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। ऐसे आयोजनों से बच्चों के प्रति अपनापन बढ़ता है और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि सेवा कार्यों को केवल एक आयोजन तक सीमित न रखकर निरंतर जारी रखने की जरूरत है।

नुक्कड़ नाटक से जनता तक पहुंचाई सरकार की योजनाओं की जानकारी

प्रयागराज, सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रयागराज महानगर के सिविल लाइंस मंडल की ओर से सुभाष चौराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। कलाकारों ने रचनात्मक प्रस्तुति के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनसे जुड़े संदेशों की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। प्रयागराज में सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न जनसंपर्क और सेवा गतिविधियां पहले भी आयोजित की गई हैं।

नुक्कड़ नाटक में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता अभियान और प्रधानमंत्री जनधन योजना सहित कई योजनाओं को विषय बनाया गया। कलाकारों ने संवाद और अभिनय के माध्यम से योजनाओं के उद्देश्यों और उनसे मिलने वाले लाभों को सरल ढंग से प्रस्तुत किया।

सुभाष चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम को देखने के लिए राहगीर और स्थानीय लोग रूके। लोगों ने रूचि के साथ कलाकारों की प्रस्तुति देखी। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जनसामान्य तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया।

वाहन चोर गिरोह के 4 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की 4 बाइक बरामद



सबसे तेज प्रयागराज

प्रयागराज। थाना दारागंज पुलिस व सर्विलांस सेल नगर टीम को वाहन चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है।

९मुखबिर की सूचना पर सरदार पटेल संस्थान पार्क थाना क्षेत्र दारागंज से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की

4 मोटरसाइकिल बरामद की गईं। बरामद बाइकों में से 2 बाइकें दारागंज से, जबकि 1 झूसी व 1 जार्जटाउन क्षेत्र से चोरी की गई थीं। गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण रितेश सिंह पुत्र शिव प्रसाद निवासी मोहम्मदाबाद बिलहरा थाना उतराव, प्रिन्स राज पटेल पुत्र रामलाल पटेल निवासी मझियारी थाना सरायममरंज, प्रिन्स यादव पुत्र राजेश कुमार यादव निवासी अहिराई थाना हंडिया, 4. सौरभ पाण्डेय पुत्र संजय पाण्डेय निवासी लाक्षागृह थाना हंडिया जनपद प्रयागराज। पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वे शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में घूमकर मोटरसाइकिलों की रेकी करते थे और मौका पाकर चुरा लेते थे, चोरी की बाइक बेचकर रुपयों से जीविकोपार्जन व शौक पूरे करते थे। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त रितेश सिंह के खिलाफ सरायममरंज, फाफामऊ, हंडिया व दारागंज थानों में चोरी के 5 मुकदमे दर्ज हैं। प्रिन्स राज पटेल के खिलाफ सरायममरंज व दारागंज में 2 मुकदमे तथा प्रिन्स यादव के खिलाफ झूसी, हंडिया व दारागंज में 3 मुकदमे दर्ज हैं। चारों अभियुक्तों के खिलाफ दारागंज पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते हुए भेजा जेल।

सबसे तेज प्रयागराज

तकनीक साथ-साथ आगे बढ़ रही हैं। हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित उत्पादों के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीक, स्टार्टअप और अन्य उद्यमों के क्षेत्रों की मौजूदगी ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था की व्यापक तस्वीर पेश की।

यूपीआईटीएस का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी कारोबारी गतिविधियां रही। पांच दिनों में हुई हजारों बी2बी बैठकों में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधे संवाद के साथ उत्पादों की गुणवत्ता, बाजार, आपूर्ति, निर्यात और कारोबारी साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इससे प्रदेश के उद्यमियों को कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पारंपरिक कारीगरी और आधुनिक

लेखक - करन कुमार की कलम से

इस धरा ने फिर, तुम्हें याद किया
इस धरा पे फिर से, आ जाओ बापू
प्रेम अहिंसा और बंधुत्व का
फिर से पाठ, पढ़ा जाओ बापू
निज सत्य शांति है के पथ चल
तुमने आजादी ढूंढी है
वो कहते हैं ये आजादी
अब सत्तर साल की बूढ़ी है
तुम नई ऊर्जा के दम भर के
फिर से जवाँ, बना जाओ बापू
इस धारा ने फिर, तुम्हें याद किया.....
राष्ट्रवाद और स्वाभिमान का,
राह तुम्हीं ने दिखाया है
आत्मनिर्भर भारत बनने को,
चरखा तुम्हीं ने चलाया है
असहयोग का आंदोलन भी,
तुमने यहीं दिखाया हैं
स्वदेशी के राह पे चल,
अंग्रेजी कपड़े जलाया हैं
ए भारत के शिल्पकार,
भारत फिर नया, बना जाओ बापू
इस धारा ने फिर, तुम्हें याद किया
.....
लोक आलोक में खो गया है



तंत्र आ गया घुटनों पर
संविधान का हाड़ मांस अब
रेंग रहा है टखनों के
अराजकता भी चरम पहुंच कर
सिर चढ़ सूती लला रहा है
सत्ता के सारे हथकड़े
विषधर बन, विष को घोल रहा है
भारत माता सिसक रही है
तुम सँसै, बन जाओ बापू
इस धारा ने फिर, तुम्हें याद किया.....
शिक्षा और नैतिकता का भी
हल बड़ा, बेहाल हुआ है
रिस्तों की, कसौटी पर भी
मानवता कंगाल हुआ है
भटक रहा है, जन मानस सब
राह नया, दिखा जाओ बापू
इस धारा ने फिर, तुम्हें याद किया.....

संपादकीय

टेलीकॉम कंपनियों पर लगी लगाम-उपभोक्ता हित में जरूरी नियमन

देश की अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र की भूमिका अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मोबाइल फोन और इंटरनेट संचार के साधन भर नहीं रह गए हैं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, व्यापार, रोजगार और सरकारी सेवाओं तक पहुंच की बुनियादी जरूरत बन चुके हैं। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों की जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सेवा की गुणवत्ता, शुल्क की पारदर्शिता, स्पैम कॉल, डेटा सुरक्षा और उपभोक्ता शिकायतों जैसे मुद्दों पर बढ़ती नियामकीय सख्ती इसी बदलती जरूरत का संकेत है।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ? से उपभोक्ताओं को सस्ते डेटा और अनेक सेवाओं का लाभ मिला है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी उठे हैं। अनचाहे कॉल और संदेश, अस्पष्ट शुल्क, खराब नेटवर्क, शिकायतों के समाधान में देरी और निजी डेटा की सुरक्षा जैसे मुद्दे लंबे समय से चिंता का विषय रहे हैं। जब कोई सेवा करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए, तब केवल व्यावसायिक लाभ पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बाजार की ताकत के साथ उपभोक्ता के प्रति जवाबदेही भी जरूरी है।

इसी संदर्भ में रिचार्ज की वैधता का सवाल खास महत्व रखता है। मोबाइल सेवा अब ऐसी जरूरत है, जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज करना संभव नहीं। 28 दिन वाले ह्यमासिक रिचार्ज को लेकर मार्च 2026 में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में सवाल उठाया था कि 12 महीनों के वर्ष में 28 दिन की वैधता वाले चक्र से उपभोक्ता को प्रभावी रूप से साल में 13 बार रिचार्ज करना पड़ सकता है। उन्होंने उन उपभोक्ताओं के लिए भी किकायती विकल्पों की जरूरत बताई, जिन्हें मोबाइल डेटा की आवश्यकता नहीं है।

यह बहस अब नियामकीय बदलाव तक पहुंच चुकी है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने 22 सितंबर 2026 को टेलीकॉम कॉन्ज्युमर्स प्रोटेक्शन अमेंडेंट रेगुलेंसंस, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए प्राधानों के तहत कंपनियों को उन वैधता अवधियों के अनुरूप वॉइस और एसएमएस ऑनली स्पेशल टैरिफ वॉउचर्स उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें 30 दिन या उससे कम अवधि वाले डेटा-बंडल प्लान शामिल हैं। इसके अलावा समान तरीख पर हर महीने नवीनीकरण वाला विकल्प और लंबी वैधता वाला कम-से-कम एक वॉइस एसएमएस ऑनली विकल्प भी उपलब्ध कराना होगा। इन वाउचर में उचित टैरिफ कटौती का भी प्रावधान है।

इस बदलाव का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि हर उपभोक्ता को समान प्रकार की सेवा की जरूरत नहीं होती। बुजुर्ग, फीचर फोन उपयोगकर्ता, सीमित डेटा इस्तेमाल करने वाले या कम आय वाले उपभोक्ताओं के लिए केवल कॉल और एसएमएस की सुविधा पर्याप्त हो सकती है। यदि उन्हें अनावश्यक डेटा के साथ बंडल प्लान लेने के लिए मजबूर होना पड़े, तो ह्यचॉइसज़ का अर्थ ही कमजोर हो जाता है। नियमन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि उपभोक्ता अपनी जरूरत के अनुसार भुगतान कर सके।

हालाँकि, 30 दिन का विकल्प उपलब्ध होना अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है। असली सवाल यह होगा कि कंपनियां इन प्लान को किननी आसानी से उपलब्ध कराती हैं और उनकी कीमत क्या रखती हैं। यदि वॉइस एसएमएस ऑनली प्लान केवल नियमों की खानापूर्ति के लिए बनाए जाएं, उनकी जानकारी आसानी से उपलब्ध न हो या उनकी कीमत डेटा वाले प्लान के मुकाबले पर्याप्त रूप से कम न हो, तो उपभोक्ता को वास्तविक लाभ सीमित रह जाएगा। इसलिए पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी इस व्यवस्था की सफलता की अनिवार्य शर्त हैं। टेलीकॉम नियमन का दायरा केवल रिचार्ज तक सीमित नहीं है। स्पैम कॉल और अनचाहे व्यावसायिक संदेश भी उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा बड़ा प्रश्न हैं। बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट और अन्य सेवाओं के नाम पर अन चाहे लगातार प्रचार संदेश कई बार धोखाधड़ी का माध्यम भी बन जाते हैं।

यूपीआई पर नए शुल्क की सच्चाई: क्या हर उपयोगकर्ता को देना होगा शुल्क?

सीए. डॉ. शंकर घनश्याम दास अंदानी
भारत में यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आज रोजमर्रा के भुगतान का प्रमुख माध्यम बन चुका है। इसलिए यूपीआई शुल्क से संबंधित किसी भी नई खबर का सीधा असर करोड़ों उपयोगकर्ताओं पर पड़ सकता है। लेकिन वर्तमान उपलब्ध आरबीआई और एनपीसीआई के आधिकारिक नियमों को देखते हुए यह कहना सही नहीं है कि हर यूपीआई उपयोगकर्ता पर नया अनिवार्य शुल्क लागू कर दिया गया है। एनपीसीआई की 2026 की यूपीआई परिपत्र सूची में कई तकनीकी और परिचालन बदलाव हैं, लेकिन सामान्य यूपीआई भुगतान पर सभी ग्राहकों के लिए नया सार्वभौमिक शुल्क घोषित होने का प्रमाण नहीं मिलता। क्या सामान्य यूपीआई भुगतान पर शुल्क है?

सामान्य बैंक खाते से बैंक खाते में यूपीआई भुगतान में ग्राहक से प्रत्येक भुगतान पर अलग से शुल्क वसूलने की व्यवस्था को नया सार्वभौमिक नियम मानना उचित नहीं है।

विशेष रूप से सोशल मीडिया या क्राइसऐप पर चलने वाली ऐसी खबरों से सावधान रहना चाहिए, जिनमें कहा जाता है कि अब हर यूपीआई लेनदेन पर निश्चित राशि काटी जाएगी। हालाँकि, कुछ विशेष सेवाओं, बैंक की अपनी शुल्क नीति या अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान में अलग शुल्क लागू हो सकता है। एनपीसीआई अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान के लिए स्पष्ट करता है कि अंतिम राशि के साथ लागू विनियम दर अथवा लागू शुल्क की जानकारी देखनी चाहिए।

व्यापारी और ग्राहक के शुल्क में अंतर
यूपीआई व्यवस्था में ग्राहक द्वारा भुगतान करने और व्यापारी से संबंधित शुल्क को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए। बैंक, भुगतान सेवा प्रदाता और व्यापारी-पक्ष पर लागू शुल्क अलग-अलग हो सकते

पूर्वजों की स्मृति, संस्कारों की विरासत और आशीर्वाद का पर्व है पितृ पक्ष

योगेश कुमार गोयल
हिन्दू धर्म में पितृ पक्ष (श्राद्ध) को बहुत अहम माना गया है। श्राद्ध का अर्थ होता है ह्यश्रद्धापूर्वकह्ह। हमारे संस्कारों और पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने को ही श्राद्ध कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु तिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया जाना जाना ही श्राद्ध है। हिन्दू पंचांग के अनुसार 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। ब्रह्मपुराण के अनुसार उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम जो भी वस्तु उचित विधि द्वारा श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दी जाए, वह श्राद्ध कहलाता है। पितृ पक्ष को हिन्दू धर्म में ह्यमहालयह्य या ह्यकनागतह्ह के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान, तर्पण कर्म और ब्राह्मण को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृ पक्ष में लोग अपने पूर्वजों को याद कर उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करते हैं। दरअसल हिन्दू धर्म में मृत्यु के पश्चात पितरों की याद में श्राद्ध किया जाता है और उनकी मृत्यु की तिथि के अनुसार ही श्राद्ध की तिथि निर्धारित की जाती है। पिंडदान करने के लिए हरिद्वार और गया को सर्वोत्तम माना गया है। वैसे हिन्दू धर्म के अलावा ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म में भी अपने पूर्वजों को याद रखने की प्रथा है। पश्चिमी जगत में जहां पूर्वजों की स्मृति में मोमबत्तियां जलाने की प्रथा है, वहीं ईसाई धर्म में व्यक्ति के निधन के चालीस दिनों पश्चात



सामूहिक भोज की रस्म की जाती है। इस्लाम में चालीस दिनों बाद कब्र पर फातिहा पढ़ने और बौद्ध धर्म में भी पूर्वजों की याद में कुछ ऐसे ही प्रावधान देखने को मिलते हैं। हिन्दू धर्म में मान्यता है कि पितृ पक्ष के दिनों में यमराज आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों के यहां जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। ऐसी ही मान्यताओं के अनुसार पितृ पक्ष के दिनों में पितर नीचे पृथ्वी पर आते हैं और बिना किसी आव्हान के अपने वंशजों के घर किसी भी रूप में जाते हैं। ऐसे में यदि उन्हें तृप्त नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा नाराज होकर अतृप्त लौट जाती है। माना गया है कि यदि पितर नाराज हो जाएं तो जिंदगी मुसीबतों से भर जाती है। इसलिए शास्त्रों में पितरों का श्राद्ध विधिपूर्वक करना जरूरी बताया गया है। मान्यता है कि यदि पितर खुशी-खुशी वापस जाते हैं तो अपने वंशजों को दिए गए उनके

भूजल संकट: भारतीय कृषि के सामने गंभीर चुनौती

डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की कृषि उपलब्धियों की चमक के पीछे एक गंभीर सच्चाई छिपी है—भूजल का तेजी से ह्रास। देश की सिंचाई का 78 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भूजल पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र भूजल निकासी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अपने पास समेटे हुए है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भूजल निकासी वार्षिक रीचार्ज से कहीं अधिक हो गई है; पंजाब में तो यह दर 152 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह स्थिति न केवल दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को खतरे में डाल रही है, बल्कि ग्रामीण असमानता, ऊर्जा की बढ़ती मांग और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण जैसे गंभीर परिणाम भी पैदा कर रही है।

इस संकट की जड़ें संरचनात्मक नीतियों और प्रोत्साहनों में निहित हैं। हरित क्रांति के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी खरीद की गारंटी ने किसानों को गेहूं-धान की एकाधिकार खेती की ओर धकेला, खासकर पंजाब और हरियाणा में। धान जैसी जल-गहन फसलें, जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल थीं नहीं हैं, बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगीं क्योंकि बाजार और नीतियां इन्हें पुरस्कृत करती रहीं। इसके साथ ही कृषि के लिए मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली बिजली ने पंपिंग लागत को नगण्य बना दिया, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त भूजल निकालने की सीमांत लागत शून्य हो गई और अंधाधुंध निकासी को प्रोत्साहन मिला। ट्यूबवेल और निजी बोरवेल का तेज विस्तार, कमजोर विनियमन और सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन की कमी ने इस स्थिति को और विगाड़ दिया।

सिंचाई पद्धतियां भी समस्या को बढ़ावा देती हैं। परंपरागत बाढ़



सिंचाई आज भी व्यापक है, जिसमें पानी की बर्बादी अधिक और दक्षता कम होती है। माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देने वाली योजनाएं मौजूद हैं, पर छोटे किसानों के लिए उच्च प्रारंभिक लागत और रखरखाव की चिंताएं अपनाने की दर को सीमित करती हैं। जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता और मानसून की अनियमितता ने किसानों को भूजल पर और अधिक निर्भर बना दिया है।

इस संकट के परिणाम खेतों से कहीं अधिक व्यापक हैं। गिरते जल स्तर के कारण किसानों को गहरे बोरवेल लगाने और अधिक शक्तिशाली पंप स्थापित करने पड़ते हैं, जिससे सिंचाई की लागत बढ़ती है और छोटे व सीमांत किसान असमानुपातिक रूप से प्रभावित होते हैं। गहरे स्तर से पानी निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे जल-ऊर्जा संबंध और तंग होता है। पारिस्थितिक दृष्टि से अति-निकासी भूमि के धंसने, तटीय क्षेत्रों में लवणीयता के प्रवेश और जल गुणवत्ता के दीर्घकालिक क्षरण का जोखिम पैदा करती है। सामाजिक स्तर पर जल की कमी कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के बीच तथा साझा नदी बेसिन वाले राज्यों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देती है।

आर्थिक रूप से सिंचाई की बढ़ती लागत खेत की लाभप्रदता को कम करती है।

इस चुनौती का समाधान केवल तकनीकी सुधारों से नहीं, बल्कि प्रोत्साहनों, संस्थानों और प्रथाओं को पारिस्थितिकीय सीमाओं के अनुरूप पुनर्संरिखित करने से ही संभव है। सबसे पहले, फसल विविधीकरण को नारे से रणनीति में बदलना होगा। पंजाब और हरियाणा में धान की खेती उसी तरह नहीं चल सकती जैसे बंगाल या असम में; मक्का, दलहन, तिलहन और बागवानी जैसी कम जल-गहन फसलों को समान बाजार गारंटी, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और मूल्य समर्थन के साथ बढ़ावा देना होगा। बिना आर्थिक व्यवहार्यता के विविधीकरण केवल कागज पर ही रहेगा। दूसरा, सिंचाई दक्षता का तेजी से विस्तार आवश्यक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के द्वापर ड्रॉप मोर क्रॉपह्ह घटक ने छोटे किसानों के लिए 55 प्रतिशत तक सब्सिडी के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों को बढ़ावा दिया है, पर कवरज अभी भी सीमित है। माइक्रो-इरिगेशन का विस्तार, धान में डायरेक्ट सीडेंड राइस और ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जैसी जल-बचत प्रथाओं को अपनाना, और लेजर लैंड लेवलिंग

विश्व हृदय दिवस : आधुनिक जीवनशैली के आघात से हृदय की रक्षा जरूरी

ललित गर्ग
हृदय केवल शरीर का एक अंग नहीं, जीवन की धड़कन है। जब तक दिल धड़कता है, तब तक जीवन में उम्मीद, संवेदना, प्रेम और कर्म की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आधुनिक सभ्यता ने जीवन को सुविधाजनक तो बनाया है, पर स्वस्थ और संतुलित बनाने में हम पीछे छूटते जा रहे हैं। हमारी तेज रफ्तार जिंदगी, तनाव, अनियमित दिनचर्या, खान-पान की बदलती आदतें, शारीरिक निष्क्रियता और निरंतर बढ़ती मानसिक बेचैनी हृदय पर ऐसा दबाव डाल रही हैं, जिसका परिणाम हृदय रोगों के बढ़ते खतरे के रूप में सामने आ रहा है। हर वर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय

महासंघ के अनुसार हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी रोग दुनिया में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण हैं और प्रतिवर्ष लगभग दो करोड़ लोगों की मृत्यु इन रोगों से होती है। वर्ष 2026 के विश्व हृदय दिवस का संदेश है—हृहृदय रोग कई बार सामने दिखाई नहीं देता, इसलिए उसने संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मैंने अपने पूर्व के आलेख ह्यभारतीय दिल खतरे मेंह्ह और हृदय स्वास्थ्य से जुड़े अन्य लेखों में बार-बार इस चिंता को व्यक्त किया है कि भारतीय समाज में बदलती जीवनशैली हमारे दिल के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। आज यह चिंता और अधिक प्रासंगिक हो गई है। हमारे आसपास ऐसे अनेक युवा दिखाई देते हैं जो



कम उम्र में ही उच्च रक्तचाप, मोटापा, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल और हृदय संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रश्न केवल यह नहीं कि हृदय रोग क्यों बढ़ रहे हैं, प्रश्न यह भी है कि हमने अपनी जीवनशैली को हृदय के विरुद्ध क्यों बना दिया है? आज सुविधा ने श्रम को कम कर दिया है। घंटों बैठकर काम करना,

मोबाइल और कंप्यूटर पर लगातार सक्रिय रहना, पैदल चलने की आदत का कम होना, देर रात तक जागना और सुबह की प्राकृतिक लय से दूर होना शरीर की जैविक व्यवस्था को प्रभावित करता है। दूसरी ओर स्वाद और सुविधा के नाम पर अत्यधिक नमक, चीनी, वसा और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का

सेवन बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू, मोटापा, उच्च रक्तचाप, बढ़ी हुई रक्तशर्करा और रक्त में वसा को हृदय रोग के प्रमुख जोखिम कारकों में गिनता है। लेकिन हृदय का संकट केवल भोजन और व्यायाम का संकट नहीं है। यह मन का संकट भी है। तनाव, प्रतिस्पर्धा, असंतोष, क्रोध, ईर्ष्या, चिंता और हर समय आगे निकलने की बेचैनी व्यक्ति के भीतर निरंतर मानसिक दबाव पैदा करती है। भौतिक उपलब्धियां बढ़ती जाती हैं, लेकिन मानसिक शांति घटती जाती है।

हमने मकानों को बड़ा किया, लेकिन मन को छोटा कर लिया; साधन बढ़ाए, लेकिन संतोष कम

कर दिया। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। इसलिए हृदय की चिकित्सा केवल अस्पताल में नहीं, जीवनशैली में भी खोजनी होगी। सुबह की सैर, नियमित व्यायाम, योग, प्राणायाम, ध्यान, पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन और नशे से पूर्ण दूरी हृदय की सुरक्षा के सामान्य नियम हैं। हृदय के अत्यधिक नमक, चीनी और संतुप्त वसा को सीमित करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जीवनशैली में ऐसे बदलाव तथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह और रक्त में बढ़े वसा का समय रहते उपचार हृदयाघात और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकता है।

प्रो. आरके जैन अरिजीत

मध्यप्रदेश की ह्यमुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवाह्ह का तीसरे दिन ही ऐसा इम्तिहान हुआ कि नाम ह्यसुगमह्ह और नतीजा ह्यगमह्ह बन गया। दो दिन पहले ढोल-नगाड़ों, कैमरों और भाषणों के बीच जिस सेवा का शुभारंभ हुआ था, उसी की पीएम ई-बस (इलेक्ट्रिक) ने तीसरे दिन इंदौर के राजवाड़ा पर राहगीरों और ऑटो/ई-रिक्षा को टक्कर मारते हुए दुकान के काउंटर तक पहुंचकर हादसा कर दिया। प्रारंभिक रिपोर्टों में ब्रेक फेल होने या चालक की गफलत की बात कही जा रही है। एक नागरिक की मौत हुई, दो-तीन लोग घायल हुए। जनता के लिए शुरू हुई सेवा तीसरे दिन अस्पताल पहुंचाने लगे, तो सवाल बस का नहीं, पूरी व्यवस्था की तैयारी का है। उद्घाटन में सरकार ने फीता काटा था, तीसरे दिन बस ने जनता की सुरक्षा का भरोसा काट दिया—सरकारी योजना का इससे करारा परिणाम क्या होगा?

बस पर नया रंग चढ़ जाने से व्यवस्था नई नहीं हो जाती। सुगम सेवा में कुछ पुरानी/सेकंड-हैंड बसों को रंग-रोगन कर उतारने के आरोप पर विपक्ष ने शुभारंभ के तुरंत बाद सवाल उठाए थे। हालांकि हादसे वाली बस नई पीएम ई-बस (इलेक्ट्रिक) बताई गई है। सवाल फिर भी वही है—नई बस हो या पुरानी, सुरक्षा कहाँ है? रंग ब्रेक की जगह चमक दिखाना जनता की आँखों में धूल झोंकना है। सड़क पर रंग नहीं, फिटनेस चाहिए। यात्री को बस में बैठते वक्त सिर्फ इतना भरोसा चाहिए कि वह सुरक्षित घर पहुँचे, सरकारी विज्ञापन में न चमके। सवाल बस के ब्रेक का नहीं, उस

व्यवस्था का है जिसने उसे सड़क पर उतारा। फिटनेस किसने दी? प्रमाणपत्र किसने जारी किया? ब्रेक किसने जाँचे? ड्राइवर को कितना प्रशिक्षण मिला? स्वतंत्र तकनीकी जाँच हुई या कागजों ने ही बस को सड़क पर भेज दिया? योजना शुरू होते ही/उद्घाटन के तुरंत बाद विपक्ष (कांग्रेस) ने पुरानी, रंग-रोगन वाली और अफिफ्ट बसों पर सवाल उठाए थे। उन सवालों को राजनीतिक श्रेणें मानकर दबाया गया या तकनीकी जाँच हुई—अब यह साफ होना चाहिए। क्योंकि ब्रेक फेल होने या हादसे के बाद जाँच करना सुरक्षा व्यवस्था नहीं, हादसे का इंतजार है। हादसा होते ही व्यवस्था का सबसे आसान हथियार निक्कलता है—हज्जीचह्ह। मौत हुई तो जाँच, लापरवाही मिली तो जाँच, कार्रवाई पूछी गई तो फिर जाँच। समीतियाँ इतनी बस चुकी हैं कि उन्हें पहिए लगा दें तो शायद शहर की परिवहन व्यवस्था ही चल पड़े। मगर जिस परिवार ने अपना सदस्य खोया, उसे रिपोर्ट नहीं, न्याय चाहिए। घायलों को सरकारी बयान नहीं, इलाज चाहिए। नागरिक को आश्वासन नहीं, यह भरोसा चाहिए कि अगली बस उसके घर से किसी की अस्पताल नहीं पहुँचाएगी। ह्यदुर्भाग्यपूर्ण घटनाह्ह कहना आसान है, जिम्मेदार तय करना मुश्किल। इसलिए व्यवस्था फिर वही करती है—जाँच बैठा देती है। बस पर पथराव और तोड़फोड़ गलत है, लेकिन जनता के गुस्से का कारण भी समझना होगा। हादसे के बाद भीड़ ने कांच फोड़े और बस में तोड़फोड़ की। जन नागरिक को लगे कि उसकी जान से ज्यादा अहमियत उद्घाटन और प्रचार को है, तो गुस्सा शीशे से आगे व्यवस्था तक पहुँचता है।

यूपी पुलिस के स्टॉल ने तीसरी बार जीता बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड

नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 में उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल ने लगातार तीसरे वर्ष ‘बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड’ हासिल किया। ट्रेड शो के हॉल नंबर-4 में लगाए गए यूपी पुलिस के स्टॉल पर पूरे आयोजन के दौरान लाखों की संख्या में विजिटर्स पहुंचे थे। स्टॉल पर योगी सरकार की यूपी पुलिस की आधुनिक कार्यप्रणाली, जनसुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जा रही तकनीक और विभिन्न पुलिस सेवाओं की जानकारी दी गई। यह अवार्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने प्रदान किया, जिसे पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम, मुख्यालय उत्तर प्रदेश राजेश कुमार यादव तथा प्रभारी मीडिया सेल, यूपी 112 करुणा शंकर सिंह ने ग्रहण किया।

उत्तर प्रदेश सूचना विभाग से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यूपी पुलिस के स्टॉल को यह सम्मान लगातार तीसरी बार मिला है। इससे पहले वर्ष 2024 और 2025 में भी ट्रेड शो में यूपी पुलिस के स्टॉल को बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस वर्ष भी स्टॉल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही और पुलिस की तकनीक एवं सेवाओं को लेकर दर्शकों ने रुचि दिखाई। पुलिस के स्टॉल पर साइबर अपराध से बचाव, यूपी 112 की सेवाओं, आधुनिक पुलिसिंग और जनसुरक्षा में तकनीक के इस्तेमाल को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-26 में यूपी पुलिस के स्टॉल को मिला लगातार तीसरा बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड पुलिस की आधुनिक कार्यप्रणाली और तकनीक आधारित सेवाओं की प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण रहा। स्टॉल के माध्यम से आम लोगों को पुलिस की सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था में तकनीक की बढ़ती भूमिका से परिचित कराया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास और बदलती पुलिस व्यवस्था की भी जानकारी दी गई। स्टॉल पर युवाओं और बच्चों ने भी पुलिस की तकनीक और सेवाओं को करीब से जाना।

राष्ट्रीय शोध योजना में पीजी मेडिकल छात्रा श्वेता कटियार का चयन

कानपुर। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल के पैथोलॉजी विभाग की पीजी छात्रा डॉ. श्वेता कटियार का भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (डीएचआर) की एचआरडी योजना में एमडी रिसर्च 2026-27 के लिए चयन हुआ है। योजना के तहत उन्हें अपनी एमडी थीसिस के शोध कार्य के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।

डॉ. श्वेता भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पीके कटियार की बेटी हैं। वह पैथोलॉजी में एमडी की पढ़ाई के साथ शोध कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर की इस योजना में उनका चयन विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। शोध के लिए मिलने वाली सहायता से उन्हें जरूरी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी।

डॉ. श्वेता अपना शोध कार्य डॉ. सिंदूरा लक्ष्मी केएल के मार्गदर्शन में कर रही हैं।

उन्हे चयन से पैथोलॉजी विभाग की शोध गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही मेडिकल छात्रों में वैज्ञानिक शोध के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यह उपलब्धि संस्थान में शोध के बेहतर माहौल को भी मजबूत करेगी।

यूपीआईटीएस 2026 में 6,500 करोड़ के 4,400 एमओयू, 15,500 करोड़ के संभावित कारोबार का बना नया रिकॉर्ड

नोएडा। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) 2026 के चौथे संस्करण का मंगलवार को निवेश, कारोबार और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के नए आयामों के साथ समापन हुआ। 25 से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित पांच दिवसीय मेगा आयोजन ने उत्तर प्रदेश के उत्पादों, एमएसएमई,

दीपावली से पहले शहर की सड़कें दुरुस्त होंगी, 20-25 दिन में काम हो पूरा : जिलाधिकारी

कानपुर। दीपावली से पहले शहर की सड़कों और सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय से काम पूरा करें। अगले 20 से 25 दिनों में सड़क सुधार का काम पूरा कराने के निर्देश जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने मंगलवार देर रात निरीक्षण के दौरान दिए। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय और मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जैन ने प्रशासन, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ शहर में रात्रिकालीन निरीक्षण किया। इस



दौरान प्रमुख मार्गों, क्षतिग्रस्त सड़कों, मरम्मत कार्यों और सफाई व्यवस्था का मौके पर जायजा लिया गया। नगर आयुक्त ने नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था और

उत्तर प्रदेश MLC चुनाव में मूल कैडर की जगह भाजपा का ‘जिताऊ’ फैक्टर पर दांव, बाहरी चेहरों पर जताया भरोसा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आगामी 23 अक्टूबर 2026 को होने वाले विधान परिषद (MLC) की स्नातक और शिक्षक खंड की सीटों के चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूची से यह साफ संदेश गया है कि पार्टी इस बार संगठन के पारंपरिक कैडर या नए चेहरों के प्रयोग से बच रही है। इसके बजाय, शीर्ष नेतृत्व ने केवल और केवल जिताऊ और अनुभवी उम्मीदवारों के फॉर्मूलें पर दांव लगाया है। इस रणनीति के तहत भाजपा ने अपने मूल कैडर के समर्पित कार्यकर्ताओं को दावेदारी को किनारे कर, बाहरी पृष्ठभूमि और विभिन्न शिक्षक व सामाजिक संठनों से जुड़े कद्दावर चेहरों पर बड़ा भरोसा जताया है।

अनुभवी और पुराने चेहरों को ही क्यों मिला मौका ?

पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव आम विधानसभा चुनावों से काफी अलग और माइक्रो-मैनेजमेंट पर आधारित होता है। इसमें महदाता सामान्य जनता न होकर केवल पंजीकृत स्नातक और शिक्षक होते हैं। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों, शिक्षक दलियनों और प्रबुद्ध वर्ग के बीच जिस चेहरे की पैठ



पहले से मजबूत है, वही सीट निकाल सकता है। यही वजह है कि भाजपा ने आंतरिक सर्वे और 'क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड' को आधार बनाकर प्रयोग करने के बजाय पुराने सू्रमाओं को ही मैदान में बनाए रखा है। उदाहरण के लिए, मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल को दोबारा टिकट दिया गया है, जबकि स्थानीय स्तर पर उनकी उम्र को देखते हुए किसी नए और युवा कार्यकर्ता को मौका देने की मांग उठ रही थी। लेकिन पार्टी ने उनके चुनावी अनुभव को ही सर्वोपरि माना।

भाजपा के प्रमुख उम्मीदवार: एक नजर में

भाजपा ने जिन महत्वपूर्ण 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, उनमें जातीय और क्षेत्रीय संतुलन के साथ-साथ जिताऊ प्रोफाइल का खास

लखनऊ में घर खरीदने का सुनहरा मौका! एलडीए फ्लैट की बुकिंग शुरू, 9 लाख रुपये से शुरूआत

लखनऊ। मोहान रोड स्थित अनंत नगर योजना में लखनऊ विकास प्राधिकरण दो अक्टूबर से अदिति अपार्टमेंट का पंजीकरण शुरू कराएगा। अपार्टमेंट में गरीबों व आम लोगों का ध्यान रखकर फ्लैट की कीमतें तय की गई हैं। इसमें सभी सुविधाएं भी होंगी। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, अदिति अपार्टमेंट में टू बीएचके 980 (अफोर्डेबल) फ्लैट की कीमत लगभग 35 लाख रुपये तय की गई है। इसी



तरह से वन बीएचके के 412 (प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0) फ्लैट हैं, इनकी कीमत लगभग नौ लाख रुपये होगी।

मजबूत छवि इससे पहले भाजपा ने लखनऊ स्नातक से अवनीश कुमार सिंह, आगरा स्नातक से मानवेंद्र प्रताप सिंह, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक से हरी सिंह हिल्लों, लखनऊ शिक्षक से उमेश द्विवेदी और मेरठ शिक्षक से श्रीचंद शर्मा के नामों को बरकरार रखा था।

मूल कैडर में सुगबुगाहट, बाहरी चेहरों का दबदबा

भाजपा की इस सूची में कई ऐसे चेहरे शामिल हैं जो मूल रूप से भाजपा या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पारंपरिक सांगठनिक ढांचे से नहीं आते, बल्कि वे शिक्षक राजनीति या अन्य दबाव समूहों के जरिए चर्चा में रहे हैं। सूची में बाहरी और शिक्षक संघठनों से जुड़े चेहरों की अधिकता के कारण पार्टी के भीतर सालों से दरी-बैनर उठाने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा भी देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं का तर्क था कि एमएलसी चुनाव के जरिए संगठन के वफादार चेहरों को सदन में भेजकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए था। हालांकि, आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी किसी भी सीट पर हार का जोखिम नहीं उठा सकती। इसलिए, वफादारी से ज्यादा 'वोट बैंक' पर पकड़ रखने वाले चेहरों को तरजीह

यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के दो उम्मीदवार घोषित, राम गोपाल यादव और धनराज नथवानी आज करेंगे नामांकन



लखनऊ। यूपी में राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। पार्टी की ओर से प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया गया है। बता दें कि दोनों उम्मीदवार आज यानी कि बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। इसकी घोषणा समाजवादी पार्टी ने

अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए प्रो. रामगोपाल यादव के साथ धनराज परिमल नथवानी को प्रत्याशी घोषित कर चौंका दिया है। रामगोपाल यादव पार्टी की वैचारिक और संगठनात्मक निरंतरता का चेहरा हैं, जबकि धनराज नथवानी की पहचान राजनीति के पारंपरिक दायरे से बाहर कारोबारी, खेल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े युवा चेहरे की है।

उएउ ज्ञानेश कुमार के आगरा आवास पर कालिख पोतने वाले 6 कांग्रेसी गिरफ्तार, दीवार पर लिखा था- 'गद्दार'



आगरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विजननगर स्थित पैतृक आवास पर सोमवार को अराजकता फैलाने के आरोप में गिरफ्तार छह कांग्रेसियों को मंगलवार को न्यायालय ने तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इनमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अनिल यादव और मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश धनगर शामिल हैं। पुलिस ने बताया मंगलवार को अनिल यादव, मुकेश धनगर और उनके साथियों ने आगरा

शहर की विजननगर स्थित कालोनी में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रवेश किया। सभी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के पैतृक आवास पर उपद्रव किया। आवास पर उनके वृद्ध माता-पिता रहते हैं। रियायती क्षेत्र में अचानक पहुंचने और हंगामे से स्थानीय कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बाद थाना हरीपर्वत पर अनिल यादव, मुकेश धनगर, राजेश कुमार, मनोज गौड़, राजेश गौतम और पंकज चौधरी के खिलाफ मुकदमा सोमवार को दर्ज किया था।

इसके बाद सभी को गिरफ्तार किया गया। मंगलवार को सभी को न्यायालय के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि विरोध का अधिकार लोकतंत्र में है पर निर्धारित स्थल और कानून की सीमा में होना चाहिए। कालोनी में बिना सूचना के प्रदर्शन से आम नागरिकों को भी असुविधा हुई मामले की जांच जारी है।

कौशांबी के बच्चों ने वीडियो वायरल कर डीएम से मांगी लाइट,10 घंटे में रोशन हुआ गांव



की अपील पर जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद बिजली विभाग की टीम ने मंगलवार देर रात चक अहमदीपुर पहुंचकर

स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू कर दिया। बताया गया कि वीडियो सामने आने के करीब 10 घंटे के भीतर ही गांव में लाइट लगाने की कार्रवाई शुरू हो गई। रात में कई स्थानों पर

स्ट्रीट लाइटें लगा दी गईं। स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद गांव की गलियां रोशन हो गईं। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बच्चों ने प्रशासन की त्वरित कार्रवाई पर खुशी जताते हुए जिलाधिकारी को धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि उन्होंने अपनी परेशानी बताई थी और प्रशासन ने उनकी बात सुनकर तुरंत समाधान करा दिया। सूचना अधिकारी रवि जायसवाल के मुताबिक, बच्चों की अपील का वीडियो संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए।

झांसी में ई-रिक्शा चालक को लूटने वाले पुलिस मुठभेड़ में एक घायल समेत चार लुटेरे गिरफ्तार

झांसी। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में कोतवाली पुलिस और स्वाट-सर्विलांस टीम ने बीते दिनों हुई ई-रिक्शा चालक से लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस मुठभेड़ में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ में एक आरोपित के पैर में गोली लगी है। जबकि उनका एक साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, 1320 रुपये नकद, दस्तावेज, एक तमंचा, तीन जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस और घटना में प्रयुक्त दो बाइक बरामद की। सीओ सिटी प्रिया सिंह ने बताया कि 28 सितंबर को सिद्धेश्वर नगर निवासी नरेंद्र ने कोतवाली में तहरीर

देकर बताया था कि वह सुबह तड़के अपना ई- रिक्शा लेकर जा रहा था तभी धोबीघाट चौकी के क्षेत्र में बड़गांव गेट के पास अज्ञात बदमाशों ने उससे दो हजार रुपये और मोबाइल फोन छीन लिया। मामले में थारा 309(4) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक माध्यमों से बदमाशों की गतिविधियों का पता लगाते हुए उनकी तलाश शुरू की। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर नगरिया पुल के पास कोतवाली पुलिस और स्वाट-सर्विलांस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में त्रश्रप वाल्मीकि

के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली और प्रभारी बाल-बाल बच गए, जबकि एक गोली उपनिरीक्षक अमित तोमर की बुलेटप्रूफ जैकेट में लगी। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान त्रश्रप वाल्मीकि, मोंटी आर्या, विकास श्रीवास्तव और राज अहिरवार के रूप में हुई है। वहीं हिमांशु उर्फ होती मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है। पुलिस ने दोनों बाइक बिना नंबर प्लेट की संभावना में मुठभेड़ और बरामदगी के बतों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

भारत विकास की गंगा : 2047 और 2014-2026 में गरीबी की बदलती तस्वीर

लेखक: सी.ए. डॉ. शंकर घनश्यामदास अनेरुनी।

भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की सफलता केवल तेज आर्थिक विकास, बड़े उद्योगों या बड़ती जीडीपी से नहीं मापी जा सकती। वास्तविक कसौटी यह है कि देश के गरीब और निम्न आय वाले परिवारों की आय, रोजगार, भोजन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर में कितना सुधार हुआ। वर्ष 2014 से 2026 के बीच उपलब्ध सरकारी तथा अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में गरीबी के कई आयामों में महत्वपूर्ण कमी आई है, लेकिन गरीबी और असमानता की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। बहुआयामी गरीबी में बड़ी गिरावट गरीबी को केवल आय से मापना पर्याप्त नहीं है। नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन-स्तर से जुड़े 12 संकेतकों को देखता है। नीति

आयोग के अनुसार बहुआयामी गरीबी 2015-16 में 24.85 प्रतिशत थी, जो 2019-21 में घटकर 14.96 प्रतिशत रह गई। आगे के लिए किए गए अनुमान में 2022-23 में यह 11.28 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। 2013-14 से 2022-23 के बीच लगभग 24.82 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी से बाहर आने का अनुमान है। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2013-14 और 2022-23 के आंकड़े प्रत्यक्ष सर्वेक्षण के बजाय उपलब्ध आंकड़ों से किए गए अनुमान हैं। इसका अर्थ है कि करोड़ों लोगों की जीवन-स्थितियों में सुधार हुआ है। बिजली, स्वच्छता, आवास, बैंकिंग, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार की गरीबी कम होने के व्यापक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। **अल्पविक गरीबी में भी कमी** विश्व बैंक के अप्रैल 2026 के भारत विकास अपडेट के अनुसार, भारत में निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रयुक्त \$4.20 (4.20 डॉलर) प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर गरीबी 2011-12 के 57.7 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 16.1 प्रतिशत रह गई। यह लगभग चार-पांचवां हिस्सा कम होने के बराबर है। विश्व बैंक के उपलब्ध विश्लेषण में अल्पविक गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज हुई है। हालांकि अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखाओं और क्रय-शक्ति समता / ट्रिपल पी (दृढ़द) के आधार पर आंकड़े बदलते हैं। इसलिए भारत में गरीब कितने हैं का एक ही प्रतिशत बताना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है। गरीबी रेखा बदलने पर गरीबी का अनुमान भी बदलता है। **ग्रामीण और शहरी भारत की वास्तविक तस्वीर** गरीबी में कमी के बावजूद ग्रामीण और शहरी भारत के बीच आर्थिक अंतर बना हुआ है। 2023-24 के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण भारत में 74,122 और शहरी भारत

में 76,996 रहा। ग्रामीण और शहरी उपभोग के बीच अंतर बताता है कि आर्थिक अवसर और उपभोग क्षमता अभी समान नहीं हैं। सबसे निचले 5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय केवल 71,677 था, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी समूह का औसत 72,376 था। दूसरी ओर, शीर्ष 5 प्रतिशत का उपभोग स्तर काफी अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि गरीबी घटने के साथ-साथ आय और उपभोग की असमानता भी 2047 की महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। **सरकार की योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा की भूमिका** गरीबी घटाने में केवल रोजगार ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं का भी योगदान होता है। नीति आयोग के अनुसार 2023-24 में मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वाले 99.7 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। एनएफएसएच-5 (नर्रररर-5) के अनुसार

2019-21 में 95.4 प्रतिशत परिवार पक्के या अर्ध-पक्के घरों में रहते थे। इसी अवधि में कम-से-कम एक सदस्य के स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों का अनुपात 41 प्रतिशत था, जो 2015-16 के 28.7 प्रतिशत से अधिक था। इन आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि गरीबी का स्वरूप केवल कम आय से आगे बढ़कर बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच के रूप में भी बदला है। **फिर भी गरीब परिवारों की समस्याएँ पूरी तरह समाप्त नहीं हुईं** रिसर्च की सच्चाई यह है कि गरीबी में कमी को गरीबी को समाप्त नहीं माना जा सकता। अभी भी बड़ी संख्या में परिवार कम आय, अस्थायी रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य खर्च, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की लागत और कृषि आय की अनिश्चिता से प्रभावित हो सकते हैं। विश्व बैंक के 2026 के विश्लेषण में भी रोजगार सृजन को आगे की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है।

राज्यसभा चुनाव: सपा से राम गोपाल और धनराज परिमल नाथवानी ने दाखिल किया नामांकन, अखिलेश यादव भी रहे मौजूद

लखनऊ समाजवादी पार्टी की ओर से राज्यसभा चुनाव के लिए प्रो. रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने प्रो. रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही प्रत्याशियों ने बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

धनराज परिमल नथवानी भारत के एक प्रमुख कॉरपोरेट लीडर और खेल प्रशासक हैं। वह वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज में ग्रुप प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं और अंबानी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके पिता परिमल नथवानी भी देश के जाने-माने



उद्योगपति और राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने लंदन के रीजेंट बिजनेस स्कूल से इंटरनेशनल बिजनेस में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की है। उन्हें पर्यावरण, वन्यजीव संरक्षण और फोटोग्राफी का शौक है और वे गुजरात के वन्यजीवों

(विशेषकर गिर के शेरों) के संरक्षण से जुड़े अभियानों में भी सक्रिय रहते हैं।

सपा ने बिछाई बिसात, बागी विधायकों को भी दिया मौका
राज्यसभा चुनाव में सपा ने अपना

तीसरा प्रत्याशी जिताने के लिए सियासी बिसात बिछा दी है। उसने न सिर्फ अपने बागी विधायकों के लिए मौका दिया है, बल्कि उन भाजपा विधायकों को भी ऑफर दिया है, जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में

युवा उद्यमी तन्मय ने वन बीएचके से शुरू किया कारोबार, आज रक्षा क्षेत्र के लिए बना रहे उन्नत कंपोजिट उपकरण

नोएडा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर किस तरह युवाओं और नए उद्यमियों को रक्षा एवं एयरोस्पेस विनिर्माण से जोड़ रहा है, इसकी प्रेरक कहानी डेटम एडवॉरंड कंपोजिट्स के सह-संस्थापक एवं उप प्रबंध निदेशक तन्मय तिवारी ने ‘यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो’ में यूपीडा के विशेष सत्र में साझा की। यूनाइटेड किंगडम (यूके) में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौटे तन्मय ने महज वन बीएचके प्लेट से अपना कारोबार शुरू किया और आज उनकी कंपनी रक्षा क्षेत्र के लिए उन्नत और हल्के कंपोजिट उपकरण तैयार कर रही है।



तन्मय तिवारी ने बताया कि उन्होंने ब्रिटेन में करीब पांच वर्ष बिताए और वहीं से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक और परास्नातक की डिग्री पूरी की। वर्ष 2020 में लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो के दौरान उन्होंने भारत के रक्षा एवं एयरोस्पेस

विनिर्माण इकोसिस्टम को करीब से देखा। डिफेंस एक्सपो में पांच दिन बिताने के बाद उन्होंने तय किया कि कंपनी की शुरूआत यूके के बजाय भारत में ही की जाएगी। उन्होंने वर्ष 2021 में परास्नातक की थीसिस पूरी करने के बाद भारत लौटकर

डेटम एडवॉरंड कंपोजिट्स की शुरूआत की। उन्होंने बताया कि कंपनी की शुरूआती गतिविधियां एक बीएचके प्लेट से शुरू हुईं। शुरूआत में कंपनी ने नागरिक क्षेत्र पर ध्यान दिया और कृषि ड्रोन, ऑटोमोबाइल तथा उच्च श्रेणी की सुपरबाइक्स में इस्तेमाल होने वाले कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर के कंपोजिट पुर्जें तैयार किए। डेटम एडवॉरंड कंपोजिट्स के सह-संस्थापक ने बताया कि नागरिक क्षेत्र से रक्षा प्रौद्योगिकी की ओर उनका रुख तेजी से हुआ। कंपनी ने आईआईटी कानपुर के संपर्क में आकर अपने कंपोजिट नमूने और परीक्षण कूपन जांच के लिए भेजे।

जौनपुर।

अपना दल (कमेरावादी) की नेता एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल मंगलवार को जौनपुर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने हिंदुस्थान समाचार प्रतिनिधि से बातचीत करते चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है और लोकतंत्र को बनाए रखने में उसकी



महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उसकी कार्यप्रणाली और दायित्व निर्वहन पर सवाल उठते हैं तो आयोग को उनका जवाब देना चाहिए।

पल्लवी पटेल ने कहा कि विपक्ष अनायास चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा रहा है। उन्होंने कहा

कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उठाए जा रहे सवालों का जवाब दें और अपनी

हाथरस : नगर पंचायत सादाबाद में बोर्ड की बैठक में हुई विकास कार्यों पर चर्चा

हाथरस।

उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में मंगलवार को नगर पंचायत सादाबाद में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इसमें नगर के विकास कार्यों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद सहमति बनाई गई। बैठक में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल तथा अधिशासी अधिकारी विकास कुमार जैन ,मुकेश कुमार सहित नगर पंचायत के सभासद मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न वाडों में कराए जाने वाले विकास कार्यों को लेकर सभासदों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। कुछ प्रस्तावों को लेकर विचार-मिलते के दौरान सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे और आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही। चर्चा के बाद कई प्रस्तावों को बोर्ड सदस्यों की सहमति से पास किया गया।नगर पंचायत अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल ने कहा कि नगर के विकास और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। पिछले समय से अधूरे या लॉबि विकास कार्य पूरा करने के लिये विशेष ध्यान दिया जाएगा। वहीं, नए प्रस्तावित कार्यों को नियमानुसार स्वीकृति के बाद कराया जाएगा।

जिला जज ने कारागार का किया निरीक्षण,बंदियों से की बात

मीरजापुर।

जिला न्यायाधीश अनुपम कुमार, जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने मंगलवार को जिला कारागार का निरीक्षण किया। इस दौरान पुरुष और महिला बैरकों में बंदियों के सामान की जांच कराई गई। तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

अधिकारियों ने विभिन्न बैरकों के साथ महिला बैरक, जेल अस्पताल और रसोईघर का निरीक्षण किया। रसोई में तैयार हो रहे भोजन की गुणवत्ता भी देखी। जेल अस्पताल में भर्ती बंदियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच कराने और जरूरत के अनुसार समय से दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने जेल प्रशासन को बंदियों को समय से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही बंदियों से कहा कि किसी को विधिक सहायता या सरकारी अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो जेल अधीक्षक के माध्यम से जानकारी दें, ताकि पात्रता के अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जा सके। निरीक्षण के दौरान जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी गई। अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाओं की जानकारी ली।

इस दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार, प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड विजय गौतम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार द्वितीय, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. कीर्ति कुमार मिश्रा, जेल अधीक्षक समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

काली माता के स्थान पर बुजुर्ग ने बांके से गला काटकर दी जान

कानपुर।

उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में बिधनू थाना क्षेत्र स्थित धीरपुर गांव में मंगलवार को बुजुर्ग ने काली माता के स्थान पर पहुंचकर बांके से गला काटकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि कुत्ते के काटने के बाद से उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। मृतक की पहचान रामआसरे (57) के रूप में हुई। वह करीब 20 वर्षों से धीरपुर गांव में अपने बहनोई मुन्नीलाल के खेत के पास झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। धीरपुर में उनकी बहन सुखरानी की ससुराल है और वहीं उनके खाने-पीने की व्यवस्था होती थी। परिवार में बहन-बहनोई के अलावा दो भांजे शैलेश कुमार और हिमांशु हैं। भांजे शैलेश ने बताया कि 14 सितंबर को गांव में घूम रहे एक कुत्ते ने रामआसरे को काट लिया था। उन्हें सीएचसी ले जाकर रैबीज का इंजेक्शन लगवाया गया और घाव का उपचार कराया गया। इसके बाद से वह काली माता के स्थान पर अपनी बलि देने की बात करने लगे थे। परिवार और ग्रामीण उन्हें समझाकर ऐसा करने से रोकते रहते थे।

बलरामपुर में सड़क दुर्घटना में मां-बेटे की मौत, महिला की हालत गंभीर

बलरामपुर।

उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में बुधवार सुबह तकरीबन आठ बजे सड़क हादसे में मां-बेटे की मौत हो गयी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की कार्रवाई में जुटी है।

नगर कोतवाली क्षेत्र बलरामपुर में मेवालाल पुलिस चौकी के निकट तेज रफ्तार कार व टैंकर में भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

देवरिया : प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में गोरखपुर, सहारनपुर और वाराणसी का दबदबा

देवरिया।

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित 70वीं प्रदेशीय माध्यमिक विद्यालयीय कुश्ती प्रतियोगिता का मंगलवार को भव्य समापन हुआ। अंडर-14, 17 और 19 वर्ष के बालक-बालिका वर्ग में खिलाड़ियों ने ग्रीको-रोमन और फ्रीस्टाइल में दमखम दिखाया। विभिन्न आयु वर्गों की ओवरऑल चैंपियनशिप में गोरखपुर, सहारनपुर, वाराणसी और अन्य मंडलों के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया।

कुश्ती प्रतियोगिता में 14 वर्षीय बालक



वर्ग में सहारनपुर मंडल 23 अंक के साथ प्रथम, मेरठ 22 अंक के साथ द्वितीय और बरेली 11 अंक के साथ

द्वितीय और वाराणसी 14 अंक के साथ तृतीय रहा। 17 वर्षीय बालक वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर 39 अंक के साथ प्रथम, मेरठ 31 अंक के साथ द्वितीय और गोरखपुर मंडल 27 अंक के साथ तृतीय रहा। बालिका वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर 21 अंक के साथ प्रथम रहा, जबकि मेरठ और मुरादाबाद ने 15-15 अंक हासिल किए। इसी तरह कुश्ती प्रतियोगिता में 19 वर्षीय बालक वर्ग में गोरखपुर मंडल 45 अंक के साथ प्रथम, मेरठ 43 अंक के साथ द्वितीय और वाराणसी 25 अंक के साथ तृतीय रहा।

बालिका वर्ग में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर 24 अंक के साथ प्रथम, मुरादाबाद 21 अंक के साथ

सुकवा-ढुकवा बांध में मिले तीन युवकों के शव, मोटरसाइकिल के आधार पर हुई शिनाख्त



पड़े होने की सूचना संबंधित जेई ने बबौना थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राहुल सिंह राठौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर तीनों शवों को पानी से बाहर निकलवाया। घटनास्थल के पास एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली, जिसका नंबर यूपी 93 बीएस 6089 बताया गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल के आधार पर जानकारी जुटाई और मृतकों के परिजनों तक सूचना पहुंचाई।

कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे परिजनों ने तीनों युवकों को शिनाख्त कर ली। मृतकों की पहचान राज पुत्र कमलेश कुमार निवासी पेंच मोहल्ला, सीपरी बाजार, रितेश परिहार पुत्र कोमल परिहार निवासी नगरा, थाना प्रेमनगर और नीरज पुत्र घनश्याम निवासी प्रेमनगर, झांसी के रूप में हुई है। बताया गया कि मृतकों में एक युवक सीपरी बाजार थाना क्षेत्र और दो युवक प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। इससे पहले दोनों थानों में युवकों की

लोकगीत महिलाओं के जीवन, श्रम और योगदान के महत्वपूर्ण दस्तावेज : प्रो. स्मिता तिवारी



लोककथाओं और आख्यानों को महिलाओं के अनुभवों के दृष्टिकोण से समझना जरूरी है। उन्होंने लोरिकायन का उदाहरण देते हुए लोक आख्यानों के सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इतिहास में महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए। कुछ परिस्थितियों में उन्हें लोकगीत गाने तक से रोका गया। ऐसे उदाहरण महिलाओं की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति और समाज में उनकी भूमिका से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल सामने लाते हैं। प्रो. जस्सल ने कहा कि लोकगीतों में महिलाओं के दैनिक

श्रम, अनुभव, जिम्मेदारियां और सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी की झलक मिलती है। इन्हें समझने से उन महिलाओं के योगदान को सामने लाया जा सकता है, जिनकी भूमिका औपचारिक इतिहास में पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं हो पाई है। उन्होंने लोक परंपराओं में संरक्षित महिलाओं की आवाज को सुनने और उनके अनुभवों को पहचानने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला अध्ययन केंद्र की निदेशक प्रो. जया कपूर के स्वागत वक्तव्य से हुआ।

चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल जायज, जवाब मिलना चाहिए : पल्लवी पटेल

लोकगीत महिलाओं के जीवन, उनके श्रम, अनुभवों और सामाजिक योगदान को समझने के महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। इनमें महिलाओं के दैनिक जीवन, जिम्मेदारियों और सामाजिक-आर्थिक भागीदारी की ऐसी स्मृतियां सुरक्षित हैं, जो पारंपरिक इतिहास लेखन में अक्सर दर्ज नहीं हो पातीं। यह बातें मंगलवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित वार्षिक व्याख्यान में अशोका विश्वविद्यालय, सोनीपत की सामाजिक मानवशास्त्र की विजिटिंग प्रोफेसर प्रो. स्मिता तिवारी जस्सल ने कही। महिला अध्ययन केंद्र की ओर से कला संकाय स्थित तिलक भवन में लोककथा और आख्यान : एक नारीवादी दृष्टि विषय पर व्याख्यान आयोजित किया गया। प्रो. स्मिता तिवारी जस्सल ने कहा कि लोक परंपराएं महिलाओं के अनुभवों और उनकी आवाज को एक ओर संरक्षित एवं आगे बढ़ाती हैं, वहीं कई बार उन्हें मौन भी करती हैं। इसलिए

जिम्मेदारी तय करें। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर युवाओं के रोजगार को लेकर भी निशाना साधा। कहा कि यदि सरकार के स्तर से पकौड़ा तलने या ई-रिक्शा चलाने को कमाई का विकल्प बताया जाता है तो इससे युवाओं के प्रति सरकार की सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और सम्मानजनक नौकरी के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है।

सहकारी बैंकों को अधिक से अधिक पैक्सों से जोड़ें, तकनीकी रूप से सक्षम बनाएं और एनपीए को शून्य पर लाएं : राम कृपाल यादव

पटना, बिहार में सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव ने सहकारी बैंकों को अधिक से अधिक पैक्सों से जोड़ने, तकनीकी एवं डिजिटल रूप से सक्षम बनाने तथा ऋण वसूली में तेजी लाकर एनपीए को शून्य पर लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए इन्हें बेहतर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और आधुनिक तकनीक के साथ कुशल सेवाप्रदाता के रूप में विकसित करना आवश्यक है। मंत्री राम कृपाल यादव मंगलवार दी पाटलिपुत्र सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पटना की वार्षिक आम सभा को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर

रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की पहुंच को अधिक से अधिक पैक्सों तक विस्तारित किया जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं आम लोगों को बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सके। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को और मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि सशक्त सहकारिता ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाने के साथ वर्ष 2047 तक विकसित बिहार की संकल्पना को बल प्रदान करेगी। रामकृपाल यादव ने सहकारी बैंकों को समय की मांग के अनुरूप तकनीकी रूप से सक्षम बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाओं में डिजिटलीकरण को तेजी से



बढ़ाया जाए और आधुनिक तकनीक के माध्यम से ग्राहकों को सरल, सुगम और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता के साथ सहकारी बैंकों को अपनी कार्यप्रणाली में और सुधार करते हुए एक प्रभावी एवं भरोसेमंद सेवाप्रदाता के रूप में विकसित होना होगा। ऋण वसूली की समीक्षा पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत मजबूत करने के लिए ऋण वसूली में तेजी लाना आवश्यक है। एनपीए को न्यूनतम स्तर पर लाते हुए इसे शून्य पर लाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। आम सभा में बैंक के अध्यक्ष रितेश कुमार द्वारा बैंक की उपलब्धियों एवं प्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक की जमा राशि बढ़कर 533.31 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 9.18 प्रतिशत रहा, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है। वित्त वर्ष 2025-26 में बैंक का एनपीए 7.40 प्रतिशत दर्ज किया गया। मौके पर मंत्री ने खाता खुलवाने में शत प्रतिशत आच्छादन करने वाले पैक्सों को सम्मानित किया। बैठक में दी पाटलिपुत्र सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अंकित कुमार, बैंक निदेशक मंडल के उपाध्यक्ष एवं निदेशकगण सहित अन्य संबंधित लोग।

सदर अस्पताल गंगवाड़ा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, डीएम ने किया शुभारंभ



दरभंगा, सदर अस्पताल, गंगवाड़ा में मरीजों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंगलवार को विभिन्न नई स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया गया। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने फीता काटकर एवं नारियल फोड़कर संस्थागत प्रसव, सिजेरियन प्रसव, शिशु चिकित्सा, हड्डी रोग, दंत चिकित्सा एवं सामान्य सर्जरी सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि नई सेवाओं के शुरू होने से ग्रामीण एवं आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को स्थानीय स्तर पर आवश्यक उपचार की सुविधा मिलेगी। गंभीर अथवा विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए मरीजों को अन्यत्र जाने की आवश्यकता भी कम होगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं चिकित्सकों को सभी सेवाओं का सुचारू एवं प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि संस्थागत एवं सिजेरियन प्रसव सेवा शुरू होने से गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिलेगी। शिशु चिकित्सा सेवा से नवजात एवं बच्चों को आवश्यक उपचार उपलब्ध होगा। वहीं हड्डी रोग, दंत चिकित्सा एवं सामान्य सर्जरी की सुविधा मिलने से संबंधित मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार मिल सकेगा। उन्होंने अस्पताल में स्वच्छता, मरीजों की सुविधा तथा समय पर जांच एवं उपचार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। चिकित्सकों एवं निर्वहन करने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के बाद डीएम ने अस्पताल परिसर में आम का पौधा लगाया। मौके पर सहायक समाहर्ता कल्पना रावत, सिविल सर्जन डॉ. अरुण कुमार, प्रभारी उपाधीक्षक डॉ. सुप्रिया नारायण, डीपीएम प्रभात कुमार राजू, डीसीएम रवि कुमार सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे।

खेल निदेशालय में व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन, प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम शुरू

दरभंगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय के आंतरिक क्रीड़ा-सभागार में समारोह आयोजित कर नवनिर्मित व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन किया गया। कुलपति प्रो. संजय कुमार चौधरी ने उद्घाटनकर्ता सह मुख्य अतिथि के रूप में व्याख्यान कक्ष का उद्घाटन किया तथा सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले खेल प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम्, राष्ट्रगान एवं दीप प्रज्वलन से हुई। निदेशक प्रो. अजय नाथ झा ने अतिथियों को पाग, चादर एवं मिथिला पेंटिंग भेंटकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल एवं शारीरिक शिक्षा निदेशालय कुलपति की स्वचन-परियोजना का साकार रूप है। शिक्षा संकायाध्यक्ष प्रो. शशि भूषण राय ने कहा कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा की आत्मा है। डॉ. पुनीता झा ने खेल और संस्कृति को एक-दूसरे का पूरक बताया। प्रो. ध्रुव कुमार ने कहा कि निदेशालय ग्रामीण एवं वंचित पृष्ठभूमि की प्रतिभाओं, विशेषकर बेटियों को आगे बढ़ने का मंच देगा। प्रो. दिलीप कुमार चौधरी ने खेल और विज्ञान के समन्वय को आवश्यक बताया। कुलपति प्रो. चौधरी ने खिलाड़ियों को अनुशासन, परिश्रम एवं खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि निदेशालय से तैयार खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक मिथिलांचल और बिहार का गौरव बढ़ाएंगे। बीपीएड एवं एमपीएड पाठ्यक्रम के लिए एनसीटीई में आवेदन प्रक्रिया चल रही है। संचालन डॉ. प्रियंका राय ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन प्रो. विजय कुमार यादव ने किया।

डीएमसीएच इमरजेंसी में युवती से दुर्व्यवहार, ड्रेसर गिरफ्तार

दरभंगा, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवम अस्पताल (डीएमसीएच) के इमरजेंसी विभाग में सोमवार शाम ड्यूटी पर तैनात एक युवती के साथ कथित छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार का मामला सामने आया। आरोप इमरजेंसी में कार्यरत एक ड्रेसर पर लगाया गया है। घटना के बाद कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में अफरातफरी की स्थिति रही। बताया जाता है कि ड्रेसर की ड्यूटी इमरजेंसी के रेड जोन में थी। इसी दौरान इमरजेंसी कॉरिडोर के समीप स्थित एक कमरे में ड्यूटी पर मौजूद युवती के साथ कथित रूप से छेड़खानी का प्रयास किया गया। युवती के विरोध कर शोर मचाने पर आसपास के अस्पतालकर्मी मौके पर पहुंचे और आरोपित ड्रेसर को पकड़ लिया। घटना की सूचना मिलने पर डीएमसीएच अधीक्षक भी इमरजेंसी पहुंचे। पीजी चिकित्सकों एवं अन्य अस्पतालकर्मीयों में घटना को लेकर आक्रोश देखा गया।

अस्पताल प्रशासन ने बेंता थाना पुलिस को सूचना दी। थानाध्यक्ष विनय मिश्रा पुलिस बल के साथ इमरजेंसी पहुंचे और युवती का फर्द बयान दर्ज किया। पुलिस आरोपित ड्रेसर को हिरासत में लेकर थाने ले गईं। थानाध्यक्ष विनय मिश्रा ने बताया कि युवती से छेड़खानी एवं दुर्व्यवहार के आरोप में ड्रेसर को सोमवार शाम गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। घटना के बाद डीएमसीएच इमरजेंसी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अस्पताल प्रशासन द्वारा मामले की विभागीय स्तर पर भी जानकारी जुटाई जा रही है।

बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दो बच्चों को कराया गया मुक्त

श्रम विभाग, बाल संरक्षण इकाई और एनजीओ के संयुक्त अभियान में हुई कार्रवाई

आरा (भोजपुर)। बाल श्रम के खिलाफ भोजपुर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत दो बच्चों को श्रम कार्य से मुक्त कराया गया। एटीएचयू शाखा, भोजपुर के नेतृत्व में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संदेश, उदवतनगर एवं गड़हनी तथा एनजीओ दिशा एक प्रयास के साथ संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया गया।



अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर बाल श्रम कर रहे दो बच्चों को चिन्हित कर मुक्त कराया गया। कार्रवाई के बाद दोनों बच्चों को विधिवत जिला बाल संरक्षण समिति को सौंप दिया गया, ताकि उनके पुनर्वास एवं सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे की कार्रवाई की जा सके। पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई है कि बच्चों से श्रम नहीं कराया जाए। बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और इससे उनका शिक्षा एवं सामान्य विकास प्रभावित होता है। कहीं भी बाल श्रम होता दिखाई देने पर इसकी सूचना संबंधित पुलिस या बाल संरक्षण इकाई को देने की अपील की गई है। पुलिस का संदेश— बाल श्रम एक अपराध है, आइए बच्चों का बचपन बचाएं।

पवार पंचायत में आवास योजना की सूची को लेकर उठे सवाल

600 से अधिक लाभुकों के नाम गायब होने का आरोप, बीडीओ से जांच व कार्रवाई की मांग

आरा/संदेश (भोजपुर)। पवार पंचायत में आवास योजना की लाभुक सूची को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहले जारी सूची में शामिल करीब 600 से अधिक लाभुकों के नाम बाद की सूची से गायब हैं। इनमें अधिकांश गरीब, दिव्यांग और वंचित वर्ग के लोग शामिल हैं। सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं व ग्रामीण



प्रखंड कार्यालय पहुंचे और मामले की जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि योजना का लाभ पक्के मकान वाले और संपन्न लोगों को भी दिया गया है।

एक ही परिवार के दो सदस्यों के नाम लाभुक सूची में शामिल होने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के अनुसार पहले और दूसरे चरण की सूची में जीरो टैगिंग वाले लाभुकों के नाम शामिल थे, लेकिन आमसभा में करीब एक हजार लोगों के नाम ही सामने आए। कुछ महिलाओं ने आवास सहायक पर पैसे लेकर नाम शामिल करने का आरोप लगाया। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायत का एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान मुखिया के साथ बीडीओ से मिला और पुनः जांच कर आवास सहायक पर कार्रवाई की मांग की।

मातंगिनी हाजरा के शहादत दिवस पर अधिवक्ताओं ने किया नमन

दरभंगा, महान स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी वीरंगना मातंगिनी हाजरा के शहादत दिवस पर मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन भवन में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित की गई। अधिवक्ता रमण जी चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अधिवक्ताओं ने मातंगिनी हाजरा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया। अधिवक्ता अरुण कुमार चौधरी ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 72 वर्षीय मातंगिनी हाजरा ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। 29 सितंबर 1942 को वह हजारों प्रदर्शनकारियों के साथ मेदिनीपुर जिले के तामलुक थाना पर तिरंगा फहराने पहुंची थीं।

संरक्षक: संजय शुक्ला,(सत्यम शिवम शुभम पीजी व लां कॉलेज टिकरी)

सलाहकार संपादक: रिजवान सैफ खान

सह संपादक: मोहम्मद दानिश फारुकी ,

सह संपादक: राम सिंह यादव

उक्त सभी पद अवैतनिक है

भागलपुर में जन सुराज की बैठक: कोशी स्नातक एमएलसी चुनाव की तैयारियों पर मंथन

भागलपुर, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को स्थानीय खलीफा बाग चौक के निकट एक विवाह भवनह्ण में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की। यह बैठक आगामी कोशी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें जन सुराज के घोषित प्रत्याशी डॉ. रजनीश रंजन के साथ भागलपुर, कोशी और पूर्णिया प्रमंडल के प्रमुख पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान चुनाव की तैयारी, नामांकन की रणनीति और प्रत्याशी के संकल्पों को हर मतदाता तक पहुंचाने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि आगामी 5 अक्टूबर को डॉ. रजनीश रंजन अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए वे स्वयं भागलपुर में मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हुए उन्होंने कहा कि इस नामांकन के साथ ही कोशी स्नातक क्षेत्र में वर्षों से चले आ रहे पारंपरिक एमएलसी जीत के एकाधिकार और सिलसिले के अंत का आगाज हो जाएगा। उन्होंने सभी समर्थकों से इस



कार्यक्रम को भव्य बनाने की अपील की। प्रशांत किशोर ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए बिहार का भला होने वाला नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशी स्नातक क्षेत्र का यह चुनाव सरकार बनाने या गिराने के लिए नहीं है, बल्कि यह समय मौजूदा सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने और उसकी मनमानी पर लगाम लगाने का है। इस महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में सुजाता प्रेम, ललन यादव, प्रमंडलीय ब्राह्मण राकेश यादव, प्रमंडलीय मीडिया प्रभारी बाबुल विवेक, भागलपुर जिलाध्यक्ष सुशील सिंह, बांका जिलाध्यक्ष दीनबंधु, लखन लाल पाठक, जमुई जिलाध्यक्ष रौबिन सिंह और मुंगेर जिलाध्यक्ष शाहब मल्लिक सहित प्रमंडल के कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय सहरसा के स्टार्टअप सेल में आइडिया बूटकैप का आयोजन

सहरसा, सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय सहरसा स्थित स्टार्टअप सेल में विद्यार्थियों एवं युवा प्रतिभागियों में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आइडिया बूटकैप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के अभिनव विचारों को उपयुक्त मंच उपलब्ध कराना तथा उन्हें व्यावसायिक रूप देने और स्टार्टअप के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना था।

कार्यक्रम में सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, आईटीआई सहरसा, पॉलिटेक्निक कॉलेज सहरसा सहित जिले के विभिन्न महाविद्यालयों एवं संस्थानों से आए प्रतिभागियों ने अपने-अपने नवाचार एवं उद्यमशील विचारों की आइडिया पिचिंग के माध्यम से प्रस्तुति दी। विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागियों के विचारों का व्यावहारिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से परीक्षण करते हुए आवश्यक सुझाव दिए गए। इस दौरान बाजार की संभावनाओं, उत्पाद एवं सेवा के विकास तथा विचारों को स्टार्टअप के रूप में आगे बढ़ाने से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई।

कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को स्टार्ट अप बिहार के उद्देश्यों, सुविधाओं एवं आवेदन



प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई। बताया गया कि बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य राज्य में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना तथा युवाओं के नवीन व्यावसायिक विचारों को स्टार्टअप के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक सहयोग एवं अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना है। प्रतिभागियों को बिहार स्टार्टअप योजना के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप के लिए उपलब्ध १10 लाख तक के इंटरैस्ट फ्री सीड फंड के संबंध में भी जानकारी दी गई।

बताया गया कि यह वित्तीय सहायता प्रारंभिक स्तर पर उत्पाद/सेवा के विकास तथा स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में उपयोगी हो सकती है। योजना के तहत निर्धारित शर्तों एवं पात्रता के अनुसार

सहायता प्राप्त की जा सकती है।

इस अवसर पर प्रतिभागियों को स्टार्टअप बिहार की आधिकारिक वेबसाइट स्टार्टअप बिहार तथा हेल्पलाइन नंबर 18003456214 के माध्यम से योजना एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य, सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा; महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, सहरसा; परियोजना प्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, सहरसा; स्टार्टअप सेल के फैकल्टी ईंचार्ज; भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, सहरसा के मुख्य प्रबंधक; विभिन्न महाविद्यालयों के सहायक प्राध्यापक सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी एवं प्रतिभागी उपस्थित रहे।

आइडिया बूटकैप के माध्यम से विद्यार्थियों एवं युवाओं को नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वित्तीय सहायता एवं सरकारी योजनाओं से संबंधित अवसरों की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में युवाओं को अपने विचारों को केवल अवधारणा तक सीमित न रखते हुए उन्हें व्यवहारिक, उपयोगी एवं संभावित व्यावसायिक उद्यम में विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

दुर्गास्थान कटिहार में नवरात्र मेले की भूमि का डाक 3 अक्टूबर को, 58 लाख रुपये न्यूनतम बोली निर्धारित

कटिहार, सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर, दुर्गास्थान (कटिहार) में आगामी शारदीय नवरात्र पूजा-2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले 10 दिवसीय मेले के लिए मंदिर परिसर की भूमि का सार्वजनिक डाक 3 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया जाएगा।

अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में शनिवार शाम 4:00 बजे होने वाली इस खुली नीलामी के लिए प्रशासन ने न्यूनतम बोली राशि 58 लाख रुपये तय की है। इस नीलामी

प्रक्रिया में भाग लेने के लिए इच्छुक संवेदकों अथवा एजेंसियों को न्यूनतम बोली राशि का 10 प्रतिशत यानी 5 लाख 80 हजार रुपये अग्रधन राशि (ईएमपी) के रूप में बैंक ड्राफ्ट के जरिए जमा कराना अनिवार्य होगा। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह नीलामी आगामी 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर (पूजा समाप्ति तक) की मेला अवधि के लिए भूमि के केवल अस्थायी उपयोग और लाइसेंस के उद्देश्य से की जा रही है।

नीलामी के दौरान बोली की शुरुआत 58 लाख रुपये से होगी और प्रत्येक अगली बोली में कम से कम 25 हजार रुपये की वृद्धि करना अनिवार्य रहेगा। अग्रधन की राशि इंडियन कोर्पोरेशन बैंक, हरदयाल रोड, कटिहार स्थित सार्वजनिक श्री दुर्गा मंदिर के खाते के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से ही स्वीकार की जाएगी और बिना ईएमपी जमा किए किसी को भी डाक प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलेगी। नीलामी की मुख्य शर्तों के तहत उच्चतम

बोली लगाने वाले सफल डाकदाता को कुल 50 प्रतिशत हिस्सा नीलामी समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर जमा करना होगा। वहीं, शेष 50 प्रतिशत राशि मेला शुरू होने के सात दिन पहले जमा करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं कराई जाती है, तो सफल बोली स्वतः रद्द कर दी जाएगी और अग्रधन की पूरी राशि जप्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में अगली पात्र बोली पर विचार किया जाएगा अथवा पुनः नीलामी आयोजित

की जा सकेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेला परिसर में दुकान, झूला, पंडाल और प्रकाश व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी विभागीय और वैधानिक अनुमतियां प्राप्त करने का दायित्व सफल डाकदाता का ही होगा। इसके साथ ही पूरे परिसर में साफ-सफाई, कचरा निस्तारण, अग्निशमन, विद्युत सुरक्षा तथा आम प्रसिद्धालुओं की सुरक्षा के पख्खा इंतजाम डाकदाता को अपने निजी खर्च पर करने होंगे।